शर्मा हार्डवेयर
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in

हिंदी दैनिक

गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

विकसित भारत समाचार

वर्ष : 13 | अंक : 05 | गुवाहाटी | बुधवार, 5 अगस्त, 2026 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

हैलाकांदी में लड़की के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के आरोप में तीन किशोर गिरफ्तार पेज 2
असम में बाढ़ से अभी भी सात जिलों की 128071 आबादी प्रभावित, दो ... पेज 3
पंजाब विधानसभा में ई-20 फ्यूल ब्लेंडिंग पॉलिसी के विरोध में प्रस्ताव पारित पेज 5
भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया-ए महिला टीम घोषित, टायला व्लेमिंक और डार्सी ... पेज 7

नगांव सीआरपीएफ कैंप में गोलीबारी

दो जवानों की हत्या के बाद एएसआई ने की आत्महत्या

जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां

नगांव (हि.स.)। असम के नगांव जिले के कातीमारी स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 34वीं बटालियन के कैंप में मंगलवार सुबह हुई गोलीबारी की घटना में दो जवानों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आरोपित एएसआई ने कथित तौर पर खुद को भी गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आंध्र प्रदेश निवासी एएसआई/जीडी बल्लानी प्रेमाबरम की मेन गेट पर ड्यूटी लगी थी। ड्यूटी के दौरान वह अपने निर्धारित सर्विस हथियार के बिना पाए गए। इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर कैंप के गार्ड रूम से एक इंसास राइफल ली और क्वार्टर गार्ड के पिछले हिस्से की ओर चले गए। पुलिस के अनुसार, सबसे पहले उन्होंने हेड कॉन्स्टेबल (एचवी/जीडी) विष्णु प्रसाद बघेल पर गोली चलाई। गंभीर रूप से घायल बघेल की मौके पर ही मौत हो गई। इसके -शेष पृष्ठ दो पर

राज्य में 9 से शुरू होगा बाढ़ प्रभावित मकानों का सर्वे : सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा- केंद्र के समक्ष उठाएंगे नगालैंड में खनन का मुद्दा

गुवाहाटी (हि.स.)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को घोषणा की कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों का विस्तृत सर्वेक्षण नौ अगस्त से शुरू किया जाएगा, ताकि प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत एवं पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराई जा सके। शिवसागर और चराईदेउ जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो दिनों से वह प्रभावित लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें हरसंभव सरकारी सहायता का भरोसा दिलाया गया है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई सूची का सत्यापन किया जा चुका है तथा लगभग एक लाख बाढ़ प्रभावित लाभार्थियों की पहचान कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विस्थापित परिवारों के लिए फिलहाल राहत शिविरों में अस्थायी व्यवस्था की गई है, जबकि पात्र लाभार्थियों के क्षतिग्रस्त मकानों का पुनर्निर्माण सरकार की पुनर्वास योजना के तहत कराया जाएगा। जलभराव की समस्या पर उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर सामान्य से अधिक होने के कारण पानी की निकासी धीमी हो गई है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कुछ स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्गों ने प्राकृतिक जल प्रवाह को बाधित किया है। इस समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) से अतिरिक्त क्रॉस-ड्रेनेज संरचनाएं बनाने का आग्रह किया जाएगा। नगालैंड में खनन गतिविधियों के कारण असम में बाढ़ की स्थिति बिगड़ने संबंधी सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि असम सरकार को दूसरे राज्य में खनन रोकने का अधिकार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि असम में कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है और इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक -शेष पृष्ठ दो पर

पूर्वोत्तर में अगले दो दिनों के दौरान भारी बारिश के आसार

नई दिल्ली (हि.स.)। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में अगले दो दिनों के दौरान भारी बारिश होने के आसार हैं। दिल्ली-एनसीआर में भी कहीं-कहीं पर अगले दो-तीन दिनों तक हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में बुधवार को सुबह से दोपहर के बीच कई जगहों पर हल्की बारिश और कुछ जगहों पर मध्यम बारिश होने के आसार हैं। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 32-34 डिग्री सेल्सियस और 23-25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। गुरुवार और शुक्रवार को भी यही स्थिति रहने के आसार हैं। छह अगस्त को अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री -शेष पृष्ठ दो पर

बाढ़ प्रभावित शिवसागर का दौरा कर मुख्यमंत्री ने की राहत कार्यों की समीक्षा

शिवसागर (हि.स.)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को बाढ़ प्रभावित शिवसागर जिले का दौरा कर राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और सरकार की ओर से हरसंभव सहायता जारी रखने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री पीयूष हजारिका, बिमल बोरा और सुषांत बूढ़ागोहाईं तथा शिवसागर के विधायक अखिल गोगोई भी मौजूद रहे। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित परिवारों से बातचीत कर नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान राहत कार्यों को और प्रभावी बनाने, क्षति का शीघ्र आकलन करने तथा प्रभावित परिवारों को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों की शिकायतें भी सुनीं और अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी पात्र लाभार्थियों तक सरकारी राहत बिना किसी देरी के पहुंचाई जाए। कार्यक्रम के दौरान प्रभावित लोगों को राहत सहायता के चेक भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने -शेष पृष्ठ दो पर

door graph Premium Quality Hinges
S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

तीन दिवसीय दौरे पर पूर्वोत्तर पहुंचे जेपी नड्डा, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा

डिब्रूगढ़ (हि.स.)। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा असम, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के तीन दिवसीय दौरे पर मंगलवार को डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे। वे आज रात्रि विश्राम डिब्रूगढ़ के मनोहारी रिसोर्ट में करेंगे। इसके बाद बुधवार को वे शिवसागर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रभावित गांवों, राहत शिविरों, क्षतिग्रस्त फसलों और मकानों का नड्डा निरीक्षण करेंगे तथा बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का जायजा लेंगे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री नड्डा बाढ़ प्रभावित नगालैंड के मोन जिले में पहुंचेंगे, जहां बाढ़ प्रभावित गांवों और राहत शिविरों का वह निरीक्षण करेंगे। साथ ही डिफेंस कॉलोनी एवं आसपास के क्षेत्रों में राहत कार्यों की समीक्षा कर प्रभावित लोगों से बातचीत करेंगे। बाद में नड्डा -शेष पृष्ठ दो पर

साल 2019 से अब तक 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत लाया गया : गृह मंत्रालय

नई दिल्ली (हि.स.)। वर्ष 2019 से अब तक 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जारी विस्तृत विवरण में कहा कि भगोड़े अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाते हुए सरकार ने प्रत्यर्पण, अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और आधुनिक तकनीक आधारित तंत्र को मजबूत किया है। मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किए जाने के बाद भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को नई गति मिली। वर्ष 2019 में एनआईए (संशोधन) अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) में संशोधन के बाद वर्ष 2020 से भगोड़ों की वापसी के लिए मिशन मोड में अभियान चलाया गया। वर्ष 2024 में लागू तीन नए आपराधिक कानूनों में भगोड़े आरोपियों के खिलाफ ट्रायल इन एब्सेंटिया (अनुपस्थिति में मुकदमा) का भी प्रावधान किया गया। गृह मंत्रालय ने कहा कि वर्ष 2004 से 2013 के बीच भारत औसतन केवल चार भगोड़े अपराधियों का ही प्रत्यर्पण करा सका था, जबकि 110 प्रत्यर्पण अनुरोध लंबित थे। उस समय सीमित प्रत्यर्पण संधियां, कमजोर कानूनी ढांचा और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी बड़ी बाधाएं थीं। मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2022 में भारत में आयोजित इंटरपोल -शेष पृष्ठ दो पर

सुप्रभात

अविनीत स्वामी के होने से तो स्वामी का ना होना अच्छा है।
- आचार्य चाणक्य

न्यूज गैलरी

म्यांमार के साथ सीमाई क्षेत्रों को लेकर बातचीत जारी : भारत

नई दिल्ली (हि.स.)। भारत ने मंगलवार को कहा कि उसके और म्यांमार के बीच कुछ सीमाई हिस्सों का निपटारा अभी बाकी है और इसको लेकर दोनों के बीच बातचीत जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पत्रकार वार्ता में मणिपुर के पास म्यांमार के साथ क्षेत्रों की अदला-बदली की खबरों पर -शेष पृष्ठ दो पर

लोकतक झील से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद

इंफाल (हि.स.)। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने मंगलवार को बिष्णुपुर जिले के मोइरांग थाना क्षेत्र स्थित लोकतक झील के सेंद्रा हिल इलाके के निकट तैरते फुमदी (वनस्पति द्वीप) से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और अन्य सामग्री बरामद की। बरामद हथियारों में एक .32 पिस्तौल, एक एसबीबीएल गन, एक .22 बोल्ट-एक्शन राइफल, एक जेफरसन राइफल, नौ स्थानीय रूप से निर्मित कार्बाइन (सीएमजी), -शेष पृष्ठ दो पर

भारत की खुफिया एजेंसी को मिली पाकिस्तान सेना की सीक्रेट जानकारी

नई दिल्ली। पाकिस्तान की सेना में बड़े बदलाव हो रहे हैं। भारत की खुफिया एजेंसियों को कई अहम जानकारी इससे जुड़ी हुई हासिल हुई है। भारत की सुरक्षा एजेंसी को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने अपने अधिकारियों, सैन्य कर्मियों को मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफार्म व्हाट्सएप का इस्तेमाल बंद करके चीन के वीचैट प्लेटफार्म पर ट्रांसफर होने के निर्देश दिए हैं। ये कदम बीजिंग और इस्लामाबाद के बीच लगातार गहराते रणनीतिक, सैन्य और तकनीकी सहयोग का एक बेहद महत्वपूर्ण संकेत -शेष पृष्ठ दो पर

दतिया उपचुनाव में हार के बाद एक्शन में भाजपा, मुख्यमंत्री आवास पर हुआ मंथन

भोपाल (हि.स.)। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार से 6,016 मतों से मिली हार के बाद भारतीय जनता पार्टी संगठन में हलचल तेज हो गई है। राजधानी भोपाल स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित मंगलवार को उच्चस्तरीय बैठक में हार के कारणों और भीतरघात की शिकायतों पर मंथन हुआ। वहीं, चुनाव परिणामों की समीक्षा के लिए दो सदस्यीय जांच समिति गठित की है। दरअसल, सोमवार को दतिया उपचुनाव के परिणामों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के भोपाल स्थित निवास पर एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, चुनाव प्रभारी भारत सिंह कुशवाह -शेष पृष्ठ दो पर

राष्ट्र को समर्पित एएसएफ की पहली स्वदेशी वैक्सीन

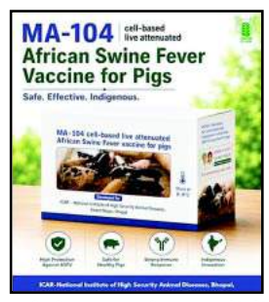

नई दिल्ली (हि.स.)। देश के पशुपालन क्षेत्र के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर (एएसएफ) के खिलाफ भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन विकसित की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को आईसीएआर के स्थापना दिवस समारोह में, इस वैक्सीन को राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह भी मौजूद रहे। अफ्रीकी स्वाइन फीवर सूअरों में फैलने वाली बेहद घातक वायरल बीमारी है, जिसमें मृत्यु दर 100 प्रतिशत तक हो सकती है। भारत में यह बीमारी पहली बार -शेष पृष्ठ दो पर

बांग्लादेश सरकार की मीडिया को चेतावनी

हसीना का भाषण छपा या प्रसारित हुआ तो होगी कार्रवाई

ढाका (हि.स.)। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सूचना एवं प्रसारण सलाहकार डॉ. जाहिद उर रहमान ने कहा कि सरकार किसी भी ऐसे मीडिया संस्थान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, जो अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भाषणों को प्रकाशित या प्रसारित करेगा। उन्होंने सचिवालय में संवाददाता सम्मेलन में आज कहा कि सरकार इस संबंध में पहले ही मीडिया के लिए सलाह जारी कर चुकी है। अगर कोई मीडिया संस्थान पहले से यह घोषणा करता है कि शेख हसीना भाषण देंगी और फिर उसे प्रकाशित या प्रसारित करता है, तो यह अदालत के आदेश की अवहेलना मानी जाएगी। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि सरकार सभी मीडिया संस्थानों को ऐसी गतिविधियों से दूर रहने के लिए फिर से याद दिला रही है। सलाहकार ने इस बात पर जो दिया कि अदालत के निर्देशों का पालन करना हर व्यक्ति और संस्था की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि अदालत के फैसलों को लागू किया जाए। अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त करते हुए सलाहकार ने कहा कि अगर अदालत -शेष पृष्ठ दो पर

पाकिस्तान और पीओजेके में मारे जा रहे आतंकी, दहशत में लश्कर-ए-तैयबा

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा अज्ञात हमलावरों की वजह से घबराया हुआ है। सोशल मीडिया पर लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकवादी रिजवान हनीफ का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में हनीफ ने माना है कि आतंकवादी संगठन के 30 से ज्यादा सदस्य मारे जा चुके हैं। उसका दावा है कि पिछले तीन-चार सालों में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) के अलग-अलग इलाकों में उनके संगठन के कई सदस्य मारे गए हैं। पेशावर, कराची, रावलपिंडी, रावालाकोट और मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने लश्कर-ए-तैयबा के 30 से ज्यादा सदस्यों को मार डाला है। यह पहली बार है जब लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े किसी आतंकवादी ने सार्वजनिक रूप से संगठन को हुए इतने बड़े नुकसान को स्वीकार किया है। हनीफ का आरोप है कि इन टारगेटेड हत्याओं के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ है, हालांकि भारत ने हमेशा इन दावों को नकारा है। वीडियो में रिजवान हनीफ को हिंदू धर्म के खिलाफ अपमानजनक और नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल करते हुए भी सुना जा सकता है। इससे पता चलता है कि कैसे -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
94350-14771

शेख हसीना के वर्चुअल संवाद से सरकार का कोई लेना-देना नहीं : विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली (हि.स.)। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि दक्षिण एशिया के विदेशी संवाददाताओं के क्लब की ओर से 5 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम से भारत सरकार का कोई लेना-देना नहीं और न ही भारत का उसमें होने वाली टिप्पणियों से कोई सरोकार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि आयोजन एक निजी मीडिया संस्था की ओर से किया जा रहा है। सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है और न ही वह मंच पर व्यक्त किए जाने वाले किसी भी विचार का समर्थन करती है। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2024 में आंदोलनों के बाद बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल हुई शेख हसीना भारत में रह रही हैं। सत्ता से बेदखल करने वाले विद्रोह की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर बुधवार को वे वर्चुअल संबोधन देने वाली हैं। हसीना दो वर्षों में पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आ रही हैं। उन्होंने घोषणा की है कि वे दिसंबर 2026 तक बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही हैं। वहीं, बांग्लादेश ने अपने यहां मीडिया को चेतावनी दी है कि वे निर्वासित पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयानों को सार्वजनिक न करें।

हैलाकांदी में लड़की के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के आरोप में तीन किशोर गिरफ्तार

हैलाकांदी। असम पुलिस ने हैलाकांदी जिले में 16 वर्षीय लड़की के साथ कथित बलात्कार और हत्या के आरोप में 17 वर्षीय लड़के सहित तीन किशोरों को गिरफ्तार किया है। जांच अधिकारियों के अनुसार, पीड़िता का कथित तौर पर आरोपियों में से एक के साथ संबंध था। असम के हैलाकांदी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-6 के पास स्थित अपने घर में शनिवार रात एक 16 वर्षीय लड़की मृत पाई गई। परिवार ने आरोप लगाया है कि उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि उन्होंने रविवार को शुरू में पांच युवकों को हिरासत में लिया था, लेकिन सोमवार तक उन्होंने 17 से 19 वर्ष की आयु के तीन किशोरों को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। उनमें से एक की उम्र साढ़े सत्रह साल है, लेकिन मामले की क्रूरता को देखते हुए, हमने अदालत से अपील की है कि उस पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाए, हैलाकांदी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अमिताभ सिन्हा ने कहा। यह घटना शनिवार रात 11 बजे कटलीचेरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले अलोइचोरा इलाके में घटी। पीड़ित परिवार ने बताया कि उस समय वे पास ही में एक रिश्तेदार के घर दावत में शामिल होने गए थे। वह भी दावत में मौजूद थी, लेकिन एक चचेरे भाई से कहासुनी के बाद वह रात 10:30 बजे घर के लिए निकल गई। हमने सोचा था कि बाद में उसके लिए कुछ खाना ले आएंगे, लेकिन जब हम लगभग एक घंटे बाद घर पहुंचे, तो उसका शव देखकर हम दंग रह गए, पीड़िता की मां ने कहा। उसने बताया कि उसका शव फर्श पर पड़ा मिला, जो लगभग पहचान से परे था। यह भयावह था; एक इंसान दूसरे इंसान, एक छोटी बच्ची के साथ इतनी क्रूरता से कैसे व्यवहार कर सकता है, उसने कहा, और आरोपी के लिए मृत्युदंड की मांग की। पीड़िता की बहन ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने हमले के बाद शरीर को क्षत-विक्षत करने के लिए बर्तनों और अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल किया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि पीड़िता के गुप्तांगों को क्षत-विक्षत कर दिया गया था और उसके शरीर पर गंभीर चोट के निशान थे, जिससे संकेत मिलता है कि उसे विभिन्न वस्तुओं से प्रताड़ित किया गया था। हैलाकांदी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, समीर दर्पण बरुआ ने कहा कि तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65(1) (16 वर्ष से कम आयु की लड़की से बलात्कार), 103(1) (हत्या) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पीओसीएसओ) अधिनियम, 2012 की धारा 6 (गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अरुणाचल प्रदेश को मिला पहला रामसर स्थल, ग्लॉव झील को मिली अंतर्राष्ट्रीय मान्यता

नई दिल्ली (हि.स.)। आर्द्रभूमि (वेटलैंड) संरक्षण के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए अरुणाचल प्रदेश की ग्लॉव झील को राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। इसके साथ ही देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 101 हो गई है। पूर्वी हिमालय में कमलांग टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित यह स्वच्छ मीठे पानी की झील जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र है। यह झील बारहमासी पर्वतीय जलधाराओं से पोषित होती है और इसके आसपास घने वन फैले हुए हैं। इस क्षेत्र और इसके जलग्रहण क्षेत्र में 150 से अधिक वृक्ष प्रजातियां तथा 49 ऑर्किड प्रजातियां दर्ज की गई हैं। सोमवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि वर्ष 2014 में देश में केवल 26 रामसर स्थल थे, जो अब बढ़कर 101 हो गए हैं। यह उपलब्धि पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन, जल एवं जलवायु सुरक्षा तथा सतत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नया रामसर स्थल प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के साथ-साथ उन समुदायों के भविष्य को भी सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिनकी आजीविका इन आर्द्रभूमियों पर निर्भर है।

बंग भवन में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी से मिले एनसीपीआई के 20 सांसद

नई दिल्ली (हि.स.)। तृणमूल कांग्रेस के अलग होकर नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में शामिल हुए 20 सांसदों ने मंगलवार को बंग भवन में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी से मुलाकात की। इस बैठक में मुर्शिदाबाद क्षेत्र के तीन मुस्लिम सांसद- अबू ताहिर, खलीलुर्रहमान और यूसुफ पठान भी शामिल रहे। बैठक में पश्चिम बंगाल के प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सांसद निशिकांत दूबे भी मौजूद रहे। एनसीपीआई के अबू ताहिर, खलीलुर्रहमान और यूसुफ पठान साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक में नहीं पहुंच रहे थे। आज भी तीनों सांसदों ने बैठक में भाग नहीं लिया। जिसके बाद तीनों सांसदों के एनसीपीआई छोड़कर दोबारा तृणमूल कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज हो चली थीं। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी से मुलाकात के दौरान तीनों सांसदों ने स्पष्ट किया कि वे एनसीपीआई में ही हैं और आगे भी पार्टी के साथ बने रहेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में वे नियमित रूप से *मंगल मिलन* बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। सुवेंदु अधिकारी को दिल्ली इसी काम के लिए बुलाया गया था। ताकि सांसदों से बात कर स्थिति ठीक करें। इस मुलाकात से पहले संसद में मीडिया से बात करते हुए नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसद और पार्टी के फ्लोर लीडर सुदीप बंद्योपाध्याय ने कहा कि उनकी पार्टी को अभी तक मान्यता नहीं दी गई है। इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी से भी बात की गई है। लोकसभा अध्यक्ष से भी बात की गई है।

किसान नेताओं ने की शिवराज सिंह से मुलाकात, एथेनॉल को बताया देश का भविष्य

नई दिल्ली (हि.स.)। अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति (एआईकेसीसी) के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। कृषि भवन में हुई इस बैठक में सभी किसान नेताओं ने एथेनॉल का समर्थन करते हुए कृषि मंत्री को सुझाव दिए। किसानों के प्रतिनिधिमंडल में पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु सहित देशभर के किसान नेता शामिल रहे। बैठक में एथेनॉल, किसानों की आय, एमएसपी, बाजार और राष्ट्रीय कृषि नीति पर चर्चा की गई। किसान नेताओं ने बैठक में एथेनॉल पर अपना रुख साफ किया और कहा कि एथेनॉल से खेत का उत्पाद सिर्फ मंडी तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पेट्रोल पंप और ऊर्जा बाजार तक जाएगा जिससे किसानों के लिए नया और मजबूत बाजार बनेगा। गन्ना, मक्का, चावल और अन्य फीडस्टॉक से एथेनॉल बनने पर किसानों को ज्यादा खरीददार मिलेंगे और फसल खराब होने या भंडारण की दिक्कत कम होगी। किसानों ने कहा कि वे एथेनॉल के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी तरह समर्थन में हैं लेकिन यह जरूरी है कि मक्का हो या गन्ना, किसी भी फसल के समुचित दाम किसानों को मिले। किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि हम चाहते हैं कि एथेनॉल नीति खेती के लिए नया रास्ता बनाए न कि हमारे लिए नई चिंता। बैठक में कई किसान नेताओं ने कहा कि एथेनॉल के नाम पर सोशल मीडिया और कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म पर कभी गाड़ियों को नुकसान बताकर, कभी किसानों को नुकसान बताकर भ्रम फैलाया जा रहा है। किसानों ने मांग की कि कृषि मंत्रालय और किसान संगठन मिलकर साफ-साफ समझाएं कि एथेनॉल से कौन-कौन सी फसलें कैसे लाभ में आएंगी और पानी वाली फसलों से सूखा-सहनशील फसलों की तरफ कैसे शिफ्ट किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी तक पहुंचने के लिए रील, छोटे वीडियो और जमीनी सभाओं के जरिए एथेनॉल का सही चित्र दिखाना जरूरी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों की बात ध्यान से सुनने के बाद कहा कि केंद्र सरकार की सोच साफ है- एथेनॉल कार्यक्रम का फायदा खेत से लेकर फ्यूल टैंक तक पूरी चेन में हो लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा किसान के हित में जाए। चौहान ने कहा कि एथेनॉल से देश की ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी और किसानों की जेब भी, हमारा जोर इसी पर है कि किसी फसल और किसी राज्य के साथ अन्याय न हो। शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में भरोसा दिया कि मक्का, चावल, गन्ना और अन्य फीडस्टॉक के दाम और मांग का संतुलन बनाए रखने के लिए नीति की समीक्षा होगी। किसान-हित, विशेषकर मक्का-किसानों के फायदे की दृष्टि से ही निर्णय लिए जाएंगे। एथेनॉल पर जो वैज्ञानिक अध्ययन और तकनीकी रिपोर्ट हैं, उनके माध्यम से नकारात्मक नैरेटिव का जवाब दिया जाएगा और किसानों के साथ मिलकर तथ्य आधारित संवाद चलाया जाएगा।

पृष्ठ एक का शेष

दो जवानों की हत्या...

बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंप आए एसआई/जीडी रामनवल सिंह यादव पर भी गोली चला दी, जिससे उनकी भी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपित ने बी/171 बटालियन के एएसआई/मैन गोविंद श्रीपुल पर भी गोली चलाई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। गोलीबारी के बाद बल्लानी प्रेमाबरम बी/171 बटालियन की बैरक में गए और कथित तौर पर खुद को गोली मार ली। उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई। घायल एएसआई गोविंद श्रीपुल को तत्काल ड्यू केयर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए गुवाहाटी रेफर कर दिया गया। मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी एसआई/जीडी रामनवल सिंह यादव, मध्य प्रदेश निवासी हेड कॉन्स्टेबल विष्णु प्रसाद बघेल तथा कथित तौर पर गोलीबारी करने वाले आंध्र प्रदेश निवासी एएसआई/जीडी बल्लानी प्रेमाबरम के रूप में हुई है। फिलहाल गोलीबारी के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। सुरक्षा अधिकारियों ने घटना के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।

राज्य में 9 से शुरू होगा ...

अध्ययन आवश्यक है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि नगालैंड स्वयं भी बाढ़ से प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां स्थानीय लोग भूमि उपलब्ध कराएंगे, वहां संवेदनशील क्षेत्रों में तटबंधों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने दीर्घकालिक बाढ़ नियंत्रण के लिए जनसहयोग को आवश्यक बताया। विपक्षी विधायक अखिल गोगोई द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए अधिक मुआवजे की मांग पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने कहा कि सरकार भी चाहती है कि लोगों को अधिक सहायता मिले, लेकिन वित्तीय संसाधनों की व्यावहारिक सीमाओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अखिल गोगोई पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बाढ़ के पानी में तैरते हुए एक वीडियो बनाया, लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने कितने लोगों को बचाया।

पूर्वोत्तर में अगले ...

सेल्सियस जबकि 7 अगस्त का अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर और उससे सटे पूर्वी भारत में कुछ जगहों पर और इसके बाद के 5 दिनों तक कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान सिक्किम, असम और मेघालय के कुछ जगहों पर बहुत अधिक भारी बारिश (21 सेमी) होने की संभावना है। केरल, तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी अगले तीन दिनों के दौरान भारी वर्षा होने का अनुमान है। उत्तर-पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में अगले 5-6 दिनों के दौरान कहीं भारी वर्षा और कहीं बहुत अधिक भारी वर्षा होने के आसार हैं। इसी दौरान अलग-अलग क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य महाराष्ट्र में बहुत अधिक भारी बारिश (21 सेमी), उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मेघालय, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, झारखंड, तटीय कर्नाटक, केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना में भी बहुत अधिक बारिश (12-20 सेमी), पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, तमिलनाडु, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश (7-11 सेमी) दर्ज की गई।

बाढ़ प्रभावित शिवसागर ...

कहा कि सरकार की प्राथमिकता बाढ़ प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत उपलब्ध कराना है। साथ ही, हुए नुकसान का विस्तृत आकलन कर आगे की आर्थिक सहायता और पुनर्वास की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने शिवसागर सहित बाढ़ प्रभावित जिलों के परिवारों के लिए अंतरिम वित्तीय सहायता की भी घोषणा की है।

तीन दिवसीय दौरे पर...

डिब्रूगढ़ लौटेंगे, जहां वह मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मा के साथ ही असम सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसके बाद नड्डा रात्रि विश्राम डिब्रूगढ़ में करेंगे। 6 अगस्त (गुरुवार) को केंद्रीय मंत्री अरुणाचल प्रदेश के केयी पन्योर जिले के याजाली जाएंगे। वहां फ्लैश फ्लड और बादल फटने से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और राहत शिविरों का निरीक्षण करेंगे तथा प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वह इटानगर में अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और फिर इसी दिन गुवाहाटी होते हुए नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

साल 2019 से अब ...

महासभा के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत किया गया। जनवरी 2025 में शुरू किए गए भारतपोल प्लेटफॉर्म के जरिए सीबीआई, राज्यों की पुलिस तथा केंद्रीय जांच एजेंसियों की 1,400 से अधिक इकाइयों को एकीकृत किया गया, जिससे सूचना साझा करने और प्रत्यर्पण प्रक्रिया में तेजी आई है। सरकार ने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत भगोड़े अपराधियों की लगभग 17,874 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गईं। वहीं, इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2022 में 40, 2023 में 100, 2024 में 107, 2025 में 112 तथा वर्ष 2026 में जुलाई तक 182 रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए जा चुके हैं। पिछले तीन वर्षों में कुल 401 रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए। मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2019 से जुलाई 2026 तक वापस लाए गए 274 भगोड़ों में हत्या, डकैती और अन्य हिंसक अपराधों के 62, यौन अपराध एवं पॉक्सो मामलों के 53, संगठित अपराध एवं गैंगस्टर मामलों के 42, मानव तस्करी एवं अपहरण के 18, आतंकवाद एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के 17, मादक पदार्थों की तस्करी के 16 तथा आर्थिक एवं वित्तीय अपराधों के नौ आरोपित शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि ऑपरेशन त्रिशूल के तहत इंटरपोल के सहयोग से उपग्रह इनपुट, डिजिटल फुटप्रिंट विश्लेषण और प्रोफाइल मैपिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर विदेशों में छिपे भगोड़ों का पता लगाया गया। कई मामलों में आरोपितों ने अपनी पहचान और नाम बदल लिए थे लेकिन भारतीय एजेंसियों ने तकनीकी सहायता से उन्हें खोज निकाला। मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका से तहव्वुर हुसैन राणा का प्रत्यर्पण भारत की कानूनी, कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्षमता का महत्वपूर्ण उदाहरण है। सरकार ने यह भी कहा कि भगोड़े अपराधियों की वापसी केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वित होल-ऑफ-गवर्नमेंट दृष्टिकोण का परिणाम है। जनवरी 2026 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी) के तहत स्थायी फोकस ग्रुप का गठन भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण संस्थागत कदम बताया गया है।

भारत की खुफिया एजेंसी ...

हो सकता है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के शीर्ष सैन्य नेतृत्व की ओर से जारी एक आंतरिक निर्देश में सभी अधिकारियों, जवानों और प्रशासनिक अधिकारियों को आधिकारिक और ऑपरेशनल संचार के लिए धीरे-धीरे व्हाट्सएप का इस्तेमाल बंद कर वीट अपनाने को कह दिया गया है। सूत्र कहते हैं कि इस फैसले के पीछे पश्चिमी मैसेजिंग प्लेटफार्म पर निगरानी, डाटा लीक और इंटरसेप्शन की आशंकाएं बहुत अहम वजह बताई जा रही हैं। पाकिस्तानी सेना का मानना है कि संवेदनशील सैन्य संचार के लिए चीन के डिजिटल इको सिस्टम का इस्तेमाल अधिक सुरक्षित और रणनीतिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि इस पूरे मामले पर जो विशेषज्ञ हैं वह कहते हैं कि वी-चेट को अपनाने से पाकिस्तान और चीन के सैन्य संचार तंत्र में अधिक तालमेल स्थापित हो सकता है। इससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभियानों खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान और साइबर समन्वय को और अधिक मजबूत करने में मदद हासिल हो सकता है। यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान और चीन के बीच रक्षा सहयोग लगातार नए आयाम हासिल कर रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में दोनों देशों के संबंध केवल लड़ाकू विमान, नौसैनिक युद्धपोत, एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे उपकरणों की खरीद तक सीमित नहीं रहे हैं। बल्कि साइबर क्षमताओं, सुरक्षित संचार नेटवर्क, साझा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और खुफिया सहयोग तक भी विस्तार हो चुका है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तानी सेना के यह कदम केवल एक मैसेजिंग ऐप बदलने का फैसला नहीं बल्कि यह चीन के साथ उसके बढ़ते डिजिटल और डिजिटल और मिलिट्री इंटीग्रेशन का स्पष्ट संकेत है। इससे भविष्य में दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य योजना, साइबर सुरक्षा, संवेदनशील सैन्य संचार में अधिक समन्वय देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से पाकिस्तान और चीन की हाल के दिनों में जुगलबंदी बनी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान और चीन की मिसाइलें बुरी तरह से भारत के आगे पिट गई, तो उसके बाद दोनों ही देश मिलकर अब नए तौर तरीके अपनाने पर लगे हैं। इसी कड़ी में माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना चीन के साथ मिलकर अब इस नए तरह के कम्युनिकेशन गेम में आना चाहती है जिसके जरिए वो अपनी सेनाओं की जानकारी को बचा सके और हैकिंग प्रूफ बना सके।

दतिया उपचुनाव में हार...

और मंत्री राव उदय प्रताप सिंह समेत करीब दो दर्जन वरिष्ठ नेता शामिल हुए। पार्टी के पराजित उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने भी बैठक में पहुंचकर संगठन के भीतर हुए कथित भीतरघात और भितरघातियों से जुड़े ऑडियो साक्ष्य प्रस्तुत किए। सूत्रों के अनुसार, शहरी क्षेत्र में पिछड़ने के कारण दतिया के कुछ स्थानीय पार्षदों और संगठन पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पार्टी सूत्रों ने यह भी बताया कि चुनाव के दौरान वायरल हुए कथित भ्रामक पोस्ट और फर्जी पत्रों की भी समीक्षा की जाएगी। ऐसे पोस्ट साझा करने वालों की सूची तैयार की जा रही है और उनके राजनीतिक संबंधों की भी जांच होगी। पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने टिकट नहीं मिलने के बावजूद भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया था। हालांकि इसके बावजूद भी पार्टी को हताशा का सामना करना पड़ा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने चुनाव नतीजों का विस्तृत विश्लेषण करने के लिए प्रदेश महामंत्री गौरव रणदीवे और वरिष्ठ नेता अंबाराम कराड़ा की दो सदस्यीय समिति बनाई है। यह समिति जमीनी स्तर पर पदाधिकारियों से चर्चा कर अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेगी। प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने कहा कि भाजपा में अनुशासन सर्वोपरि है। कोई भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी, चाहे वह किसी भी दायित्व पर हो, संगठन के अनुशासन से ऊपर नहीं है। अनुशासन के विरुद्ध कार्य करने वालों के खिलाफ संगठन के नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जायेगी। वहीं, चुनाव परिणाम के बाद पार्टी के भीतर से भी स्वर उठने लगे हैं। पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने सोशल मीडिया एक्स पर *आत्ममंथन का समय...* लिखकर संकेत दिए, वहीं टीकमगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष उमिता राहुल सिंह ने भी अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि जब कार्यकर्ता की जगह अधिकारी यह कहने लगें कि हमारी पहुंच ऊपर तक है, तब परिणाम विपरीत ही आते हैं। चुनाव परिणाम में मिली हार के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि है और भाजपा इस जनादेश का पूरी विनम्रता से सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि पार्टी अपनी कमियों का आकलन कर भविष्य में और अधिक मजबूती के साथ जनता के बीच जाएगी। गौरतलब है कि इस उपचुनाव में कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,016 वोटों के अंतर से शिकस्त दी है। कांग्रेस के घनश्याम सिंह को 66,757 (42.39 फीसदी) वोट प्राप्त हुए, जबकि भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को 60,741 (38.57 फीसदी) वोट हासिल हुए। इस हार के बाद भाजपा अपने संगठनात्मक ढांचे को दुरुस्त करने में जुट गई है।

राष्ट्र को समर्पित ...

वर्ष 2020 में सामने आई थी। इसके बाद कई राज्यों, खासकर पूर्वोत्तर भारत में बड़े पैमाने पर सूअरों की मौत हुई और हजारों पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जानकारी दी कि भारत में एएसएफ के फैलने का आर्थिक असर काफी ज्यादा रहा है। 2020 और 2021 में असम में जब यह बीमारी पहली बार फैली, तो सूअरों की मौत और उन्हें मारने की वजह से लगभग 276 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मिजोरम में, 2025 तक एएसएफ के फैलने से 11,382 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं, जिससे लगभग 982 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। इन घटनाओं ने बीमारी से निपटने की तैयारी को मजबूत करने, किसानों की आजीविका की रक्षा करने और देश के सूअर पालन सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए एक असरदार घरेलू समाधान की तत्काल जरूरत को उजागर किया है। आईसीएआर के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान, भोपाल के वैज्ञानिकों ने एमए-104 सेल लाइन आधारित लाइव एटेन्यूएटेड एएसएफ वैक्सीन विकसित की है। यह वैक्सीन बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयुक्त है और इससे निर्माण लागत भी कम होगी। वैक्सीन का सुरक्षा, प्रभावशीलता, आनुवंशिक स्थिरता और फील्ड ट्रायल सहित सभी आवश्यक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। इसे 8 सप्ताह से अधिक आयु के स्वस्थ सूअरों को 1 मि.ली. की खुराक के रूप में लगाया जाएगा तथा 14 दिन बाद बूस्टर डोज दी जाएगी। आईसीएआर के मुताबिक इस वैक्सीन से सूअरों की मृत्यु दर में कमी आएगी, किसानों की आर्थिक हानि घटेगी और देश की जैव सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। साथ ही, भारत सस्ती एएसएफ वैक्सीन के वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में भी उभर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपलब्धि पशु स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और *आत्मनिर्भर भारत* अभियान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हसीना का भाषण छपा ...

का आदेश नहीं होता तो वह हसीना के भाषणों के प्रसारण पर रोक लगाने का समर्थन नहीं करते। डॉ. जाहिद उर रहमान ने कहा कि अगर कोई अदालत के आदेश से असहमत है, तो उसे सक्षम अदालत में चुनौती देने का अधिकार है, लेकिन जब तक आदेश लागू है, सभी को इसका पालन करना होगा। इस सवाल के जवाब में कि सरकार को पूर्व पुलिस महानिरीक्षक बेनजीर अहमद की जमानत के बारे में दो-तीन दिन बाद क्यों पता चला, जाहिद ने कहा कि वह तुरंत कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। एक अन्य सवाल के जवाब में कि क्या प्रशासन और अन्य संस्थाओं में पिछली सरकार का प्रभाव अभी भी बना हुआ है? सलाहकार ने कहा कि शेख हसीना की सरकार का पतन और 5 अगस्त को उनका देश छोड़कर जाना बांग्लादेश के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्ष के दौरान प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले सभी अधिकारियों को रातों-रात बदलना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार से जुड़े कई लोग अभी भी प्रशासन सहित विभिन्न संस्थाओं में काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ हटाना संभव नहीं है। इस प्रक्रिया में समय लगता है। महत्वपूर्ण है कि शेख हसीना के नई दिल्ली में होने वाले संभावित वर्चुअल संबोधन को लेकर ढाका ने भारत से स्पष्टीकरण मांगा है। नई दिल्ली में पांच अगस्त को फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया के आयोजित एक कार्यक्रम में हसीना के शामिल होने की चर्चा है। ढाका ने भारतीय उच्चायुक्त के समक्ष कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और कहा है कि भारतीय जमीन से राजनीतिक गतिविधियों या संबोधन से दोनों देशों के संबंधों की सकारात्मक गति प्रभावित हो सकती है। भारतीय पक्ष ने स्थिति पर सतर्क रहने और मामले की जांच करने का भरोसा दिया है।

पाकिस्तान और पीओजेके ...

आतंकवादी संगठन नफरत फैलाने और लोगों को कट्टरपंथ की ओर धकेलने के लिए धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाते हैं। पाकिस्तान ने पहले भी भारत पर अपनी सीमा के अंदर आतंकवादियों की हत्याओं के पीछे होने का आरोप लगाता रहा है। जनवरी 2024 में, तत्कालीन विदेश सचिव मुहम्मद सायरस सज्जाद काजी ने दावा किया था कि भारतीय एजेंसियां पाकिस्तान में सीमा-पार टारगेटेड हत्याओं में शामिल थीं। भारत ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। इसके बाद, अप्रैल 2024 में ब्रिटिश अखबार की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2020 से पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों द्वारा लगभग 20 आतंकवादियों और उग्रवादियों को मार दिया गया है। मारे गए लोगों में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिज्बुल मुजाहिदीन से जुड़े लोग शामिल बताए जाते हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों और कथित खुफिया सूत्रों का हवाला देते हुए, रिपोर्ट में दावा किया गया कि इन घटनाओं में भारतीय एजेंसियों की भूमिका थी। हालांकि, भारत के विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को खारिज करते रहा है। विदेश मंत्री एस। जयशंकर ने भी कहा कि दूसरे देशों में टारगेटेड हत्याएं करना भारत सरकार की नीति नहीं है।

म्यांमार के साथ सीमाई ...

प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सीमा पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनका अभी तक निपटारा नहीं हुआ है और उन विशेष क्षेत्रों पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। उल्लेखनीय है कि लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में विदेश मंत्रालय बता चुका है कि भारत और म्यांमार के बीच कोई सीमा विवाद नहीं है। हालांकि, मणिपुर क्षेत्र में भारत-म्यांमार सीमा पर नौ अनसुलझे सीमा स्तंभ (बीपी) मौजूद हैं।

लोकतक झील से भारी ...

दो स्थानीय रूप से निर्मित एमपी-5 हथियार, तीन स्थानीय निर्मित लाथोडे गन, दो पोम्पी गन, छह आईईडी पैकेट तथा अन्य सहायक सामग्री शामिल है। बरामद सामग्री को कब्जे में लेकर सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। एक अन्य कार्रवाई में एनडीपीएस अधिनियम के तहत सेनापति थाना में दर्ज एक मामले में पुलिस ने अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के दियुन निवासी 32 वर्षीय दीप ज्योति गोगोई को गिरफ्तार किया। उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सेनापति थाना लाया गया है।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : प्रदीप शील ● सहयोगी संपादक : रवि शंकर चौधरी ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**

10 करोड़ नशा मुक्त प्रतिज्ञा मेगा अभियान का राज्यस्तरीय शुभारंभ

गुवाहाटी (हिंस)। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मंगलवार को गुवाहाटी में *10 करोड़ नशा मुक्त प्रतिज्ञा* मेगा अभियान के राज्यस्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित यह राष्ट्रव्यापी अभियान 6 से 20 अगस्त तक चलेगा। राज्यपाल ने कहा कि नशाखोरी समाज और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती है तथा इसके उन्मूलन के लिए जनभागीदारी आवश्यक है। उन्होंने ब्रह्मकुमारी संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए विश्वास जताया कि असम *नशा मुक्त भारत अभियान* और विकसित भारत 2047 के संकल्प को जनआंदोलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

असम में बाढ़ से अभी भी सात जिलों की 128071 आबादी प्रभावित, दो और शव मिले, मृतकों का आंकड़ा पहुंचा 87

गुवाहाटी (हिंस)। असम में बाढ़ से अभी भी सात जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं। प्रभावित जिलों में चराईदेव, शिवसागर, धेमाजी, गोलाघाट, बिश्वनाथ, जोरहाट और लखीमपुर शामिल हैं। बाढ़ से इन जिलों के 24 राजस्व मंडलों के कुल 380 गांवों की 128071 आबादी प्रभावित है। एवं 14230.148 हेक्टेयर कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। बाढ़ की विनाशलीला ऊपरी असम के मुख्य रूप से चार जिलों शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट एवं गोलाघाट में देखी जा रही है। सबसे अधिक शिवसागर जिले की स्थिति सबसे अधिक खराब है। पानी और कीचड़ लोगों के घरों में और रास्तों में अभी भी भरा हुआ है। सरकार के साथ ही स्वयंसेवी संगठन एवं अपने स्तर पर लोग प्रभावित इलाकों में पहुंचकर राहत कार्य में अपनी मदद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा उपरी असम में बीती 2 अगस्त से डेरा डाले हुए हैं। राहत कार्य को तेज करने के लिए सभी पहलुओं की निगरानी कर रहे हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तीन अगस्त के आंकड़ों के अनुसार, धनसिरि नदी (नुमलीगढ़) इलाके में खतरे के निशान से अभी भी ऊपर बह रही है। इस बीच सोमवार को शिवसागर जिले से दो और लोगों के शव बरामद हुए। इस तरह बाढ़ से राज्य में मृतकों की कुल संख्या 87 पहुंच गई है। सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 38 राहत शिविर एवं 17 राहत वितरण केंद्र समेत कुल 55 शिविर क्रियान्वित रखे हैं। राहत शिविरों में 11066 लोग आश्रय लिए हुए हैं। जबकि राहत वितरण केंद्रों पर 184 गैर-शिविर निवासी राहत प्राप्त कर रहे हैं। बाढ़ में राहत एवं बचाय अभियान में एसडीआरएफ, सेना/अर्धसैनिक बल, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ, एयर फोर्स, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं (एफ एंड ईएस), सर्कल कार्यालय/स्थानीय प्रशासन, नागरिक सुरक्षा/प्रशिक्षित स्वयंसेवक और अग्निशमन विभाग जुटा हुआ है। इस बीच बाढ़ प्रभावित इलाकों में शनिवार को राज्य सरकार ने कुल 76 मेडिकल टीमों को तैनात किया। इस दौरान 23 नावें भी राहत कार्य में जुटी रहीं। बाढ़ से बड़े पैमाने पर सड़क, पुल एवं अन्य आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुंचा है। इसकी मरम्मत के लिए सरकार लगातार समीक्षा बैठक कर हालात का जायजा ले रही है।

निर्माणाधीन तामुलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का स्वास्थ्य मंत्री अशोक सिंघल ने किया निरीक्षण

तामुलपुर (हिंस)। असम के स्वास्थ्य मंत्री अशोक सिंघल ने मंगलवार को तामुलपुर के संरक्षक मंत्री जयंत मल्ल बरुवा के साथ निर्माणाधीन तामुलपुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निरीक्षण किया। लगभग 170 बीघा भूमि में बन रहे इस मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के आत्मनिर्भर, प्रगतिशील और सुरक्षित असम के विजन की झलक अब दूर-दराज के क्षेत्रों में भी दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि तामुलपुर में इतने आधुनिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कभी लोगों की कल्पना से भी परे थी और यह मुख्यमंत्री द्वारा किए गए वादों को पूरा करने का प्रमाण है। सिंघल ने बताया कि मेडिकल कॉलेज का लगभग 90 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और शेष 10 प्रतिशत कार्य अगले चार महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद अस्पताल की बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) की स्वीकृति मिलने के बाद अगले वर्ष मेडिकल कॉलेज में शैक्षणिक सत्र भी शुरू होने की उम्मीद है। निरीक्षण के दौरान गोरेश्वर के विधायक विक्टर कुमार दास, बीटीसी के उप प्रमुख बिजित गौरा नर्जारी, कार्यकारी सदस्य लक्षी दास, वरिष्ठ भाजपा नेता सोमनाथ बसुमतारी, तामुलपुर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बिजित कुमार दुवरा, जिला आयुक्त सिमी करण, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुमन चक्रवर्ती सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रथम वाहिनी एसएसबी की मैराथन और देशभक्ति दौड़ आयोजित

गुवाहाटी (हिंस)। गुवाहाटी के सोनापुर स्थित प्रथम वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव और *हर घर तिरंगा* अभियान के अंतर्गत कमांडेंट सुनील कौशिक के मार्गदर्शन में *एफ* कंपनी, मोरिगांव द्वारा मिनी मैराथन और देशभक्ति दौड़ का आयोजन किया गया। वहीं *ए* समवाय, रोवता द्वारा रोवता बागान रेलवे स्टेशन परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। पहले कार्यक्रम का शुभारंभ *एफ* कंपनी के कंपनी कमांडर एवं सहायक कमांडेंट इम्थी जामिरल द्वारा किया गया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्होंने *हर घर तिरंगा* अभियान के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि यह अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करता है। उन्होंने सभी से अपने घरों पर गर्व के साथ तिरंगा फहराने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आग्रह किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एसएसबी के कार्मिकों और स्थानीय नागरिकों में देशभक्ति की भावना जागृत करना, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान बढ़ाना, शारीरिक फिटनेस को प्रोत्साहित करना और स्वस्थ एवं अनुशासित जीवनशैली को अपनाने के लिए प्रेरित करना था।

प्रेगमैटिक एकेडमी ने मनाया 23वां स्थापना दिवस, बाढ़ पीड़ितों के लिए एक लाख देने की घोषणा

कामरूप (हिंस)। कामरूप जिला के रंगिया स्थित प्रेगमैटिक एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सप्ताहव्यापी विद्यालय सप्ताह समारोह का समापन मंगलवार को 23वें स्थापना दिवस एवं नवागत स्वागत समारोह के साथ हुआ। स्थानीय हरदत्त-वीरदत्त भवन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रेगमैटिक शैक्षिक न्यास के अध्यक्ष महसेन अली ने की। कार्यक्रम में असम लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष भारतभूषण देवचौधुरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि शोधार्थी एवं युवा वक्ता प्रदीप भागवती ने विशिष्ट वक्ता के रूप में अपने विचार रखे। इस अवसर पर प्रेगमैटिक शैक्षिक न्यास के प्रबंध निदेशक अनिल दत्ता ने स्थानीय विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष में ऊपरी असम के बाढ़ प्रभावित जिलों के लोगों की सहायता के लिए एक लाख रुपये का योगदान देने की घोषणा की। समारोह में गत वर्ष की हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (एचएसएलसी) परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 55 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा विद्यालय की दो मेधावी छात्राओं जेनिस जेनिंगम और हर्षिता तालुकदार को पांच-पांच हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। कार्यक्रम में प्रेगमैटिक शैक्षिक न्यास के प्रबंध निदेशक अनिल दत्ता, सचिव डॉ. द्विपेश चंद्र भट्टाचार्य, न्यास की पदाधिकारी नमिता दत्ता, विद्यालय के प्राचार्य दीपज्योति बरुवा, मदन मोहन कलिता, नवज्योति कलिता, कृष्ण कलिता सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

चैंपियन मेकर अकादमी के पदक प्राप्त खिलाड़ियों का सम्मानित किए गए

विश्वनाथ (विभास)। सतिया चैंपियन मेकर एकादमी से परीक्षण प्राप्त खिलाड़ियों ने छत्तीसगढ़ में अनुष्ठित सीबीएससी फॉर ईस्ट जन जूडो प्रतियोगिता में 5 पदक जीत कर सतिया पहुंचने पर सभी सतियावासियों ने सम्मान समारोह का आयोजन किया गया हैं। समारोह की सभा की अध्यक्षता सतिया नागरिक सभा के अध्यक्ष भव शौकिया ने की ओर सभा का संचालन हेमांग हजारिका ने किया। नागरिक सभा के सचिव विवेक दुवारा ने सभी खिलाड़ियों को उत्साहित करते हुए भाषण दिया। चैंपियन मेकर एकादमी के परिक्षक हदयानंद दास की प्रशंसा की ओर सभी खिलाड़ियों को आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स भाग लेकर नाम रोशन करने की सलाह दी उक्त प्रतियोगिता में सतिया चैंपियन मेकर एकादमी के सात खिलाड़ियों ने भाग लिया था जिसमें 5 खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं जिसमें 14 साल 45 किलो शाखा में

प्रथम गीतार्थ कलिता को स्वर्ण पदक दूसरा 14 साल 50 किलो शाखा में देवानिभ बरमुदोई स्वर्ण पदक 17 साल 45 किलो शाखा में भूमिष्ठा दास स्वर्ण पदक हासिल किया है वहीं उक्त प्रतियोगिता में देवपर्ण मेधी ने अपनी शाखा में सिल्वर पदक वही अंगसुमान बोरा को कांस्य पदक हासिल किया था मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित नदुवार के विधायक पद्म हजारिका ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देने के साथ प्रशंसा पत्र के गुलाम गमछा ओढ़ाकर नगद धन राशि के साथ सम्मानित किया इसी के साथ सतिया नागरिक सभा बोनिक संस्था क्रीड़ा संस्था नगरपालिका आंचलिक पंचायत ज्ञान विकास अकादमी की ओर से भी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया सभी संस्थाओं को पद्माधिगण सहित अंचल के बहुत से गणमान्य व्यक्तियों के साथ खिलाड़ियों के अभिभावक उपस्थित थे।

जनगणना 2027 को लेकर बीटीसी सचिवालय में स्व-गणना प्रशिक्षण, हेल्प डेस्क स्थापित

कोकराझाड़ (हिंस)। कोकराझाड़ में जनगणना 2027 की तैयारियों के उद्देश्य से आज बोड़ोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) परिषद

सभा ऑडिटोरियम हॉल में स्व-गणना प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जीएडी, बीटीसी द्वारा कोकराझाड़ जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया। प्रशिक्षण में बीटीसी सचिवालय और बीटीसी परिषद सभा के कुल 144 अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान दो मास्टर ट्रेनरों ने प्रतिभागियों को ऑनलाइन स्व-गणना प्रक्रिया, आवश्यक दिशा-निर्देश और गणना के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों को बताया गया कि जनगणना 2027 के तहत स्व-गणना की सुविधा 2 अगस्त से 16 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। इस अवसर पर जीएडी, बीटीसी के सचिव भास्कर ज्योति मंता ने कहा कि जनगणना 2027 को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सरकार सभी आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय और आम जनता की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने पात्र नागरिकों से निर्धारित समयसीमा के भीतर अपनी स्व-गणना पूरी करने की अपील की। वहीं, अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों को स्व-गणना प्रक्रिया में सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बीटीसी सचिवालय में स्व-गणना सहायता डेस्क भी स्थापित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने गीतकार आनंदिराम दास की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

गुवाहाटी (हिंस)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को प्रख्यात असमिया गीतकार आनंदिराम दास की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में आनंदिराम दास को असमिया संगीत और साहित्य के आकाश का उज्ज्वल नक्षत्र बताते हुए कहा कि उनके गीतों ने असमिया संगीत को समृद्ध किया है और अनेक पीढ़ियों के हृदय को स्पर्श किया है। उन्होंने कहा कि शब्दों की मधुरता, भावनाओं की गहराई और सांस्कृतिक चेतना से समृद्ध उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक हैं। मुख्यमंत्री ने उनकी पुण्यतिथि पर महान गीतकार के अमूल्य योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए उन्हें सादर नमन किया।

धुबड़ी से पत्रकारों का एक दल आवश्यक सामग्री लेकर शिवसागर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचा

धुबड़ी (विभास)। धुबड़ी से शिवसागर तक 643 किलोमीटर की दूरी तय करके धुबड़ी के पत्रकारों का एक प्रतिनिधि दल बाढ़ प्रभावित लोगों के पास पहुंचा। इन पत्रकारों में सेलीम शेख, असराफुल और सामाजिक कार्यकर्ता सिमुल सरकार सहित कई अन्य शामिल हैं। जानकारी के अनुसार रूहिल लर्निंग हब फाउंडेशन पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं की पहल पर और धुबड़ी निवासियों के सहयोग से शिवसागर में बाढ़ पीड़ितों के बीच सभी आवश्यक सामग्री वितरण की गई। धुबड़ी के लोगों के द्वारा दिए गए दान और योगदान को इस चार सदस्यवाली पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता के दल के माध्यम से बाढ़ प्रभावित लोगों तक पहुंचाया। मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने चावल, दाल, आलू, चीनी, नमक, बिस्किट, मोदी सरसों का तेल, लहसुन, सोयाबीन, चायपत्ती, मोमबत्ती माचिस आदि सामग्रियों का इन बाढ़ प्रभावितों के बीत वितरण किए गए। वहीं महिलाओं, बच्चों और पुरुषों के लिए नए कपड़े भी वितरण किए गए।

द इंडोर एरिना 2.0 का मायुंम नगांव समृद्धि शाखा का सफल आयोजन

नगांव (निसं)। मारवाड़ी युवा मंच, नगांव समृद्धि शाखा द्वारा शनिवार नगांव स्थित अग्रसेन भवन में *द इंडोर एरिना-2* का भव्य आयोजन किया गया। लगभग 4 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में नगांव की अनेक महिलाओं एवं बच्चों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया। वहीं शाखा की सभी सदस्याओं ने भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी निष्ठा एवं मेहनत से अपना योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों और महिलाओं ने लूडो, शतरंज, कैरम बोर्ड, हाउजी, मेमोरी टेस्ट, एक मिनट गेम्स म्यूजिकल चैयर पोट गेम्स सहित कई मनोरंजक खेलों का आनंद लिया। सभी प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह के साथ खेलों में भाग लेकर कार्यक्रम को यादगार बना दिया। खेलों के साथ-साथ सभी के लिए स्वादिष्ट खान-पान की भी विशेष व्यवस्था की गई, जिससे कार्यक्रम का आनंद और भी बढ़ गया। द इंडोर एरिना-2 केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा, बल्कि आपसी मेल-मिलाप, पारिवारिक जुड़ाव और आनंदमय वातावरण का एक सुंदर उदाहरण भी बना। कार्यक्रम की शानदार सफलता के लिए समृद्धि शाखा की समस्त टीम, संयोजिका पूनम एवं सभी प्रतिभागी को अध्यक्ष स्वेता जयदीप अग्रवाल ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने की जनगणना-2027 की स्व-गणना, लोगों से सक्रिय भागीदारी की अपील

गुवाहाटी (हिंस)। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मंगलवार को लोक भवन में ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल के माध्यम से जनगणना-2027 के लिए अपनी स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) पूरी की। इस अवसर पर उन्होंने राज्य के लोगों से देश की इस महत्वपूर्ण सांख्यिकीय प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। राज्यपाल ने स्व-गणना प्रक्रिया को सरल, सुरक्षित, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल बताते हुए कहा कि इसे कुछ ही मिनटों में आसानी से पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह डिजिटल सुविधा नागरिकों को अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाने के साथ-साथ सटीक और विश्वसनीय राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने में योगदान देने का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि जनगणना प्रभावी योजना निर्माण, सुशासन और सार्वजनिक सेवाओं के समान वितरण की आधारशिला है। सटीक जनगणना आंकड़े कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण, संसाधनों के संतुलित आवंटन तथा साक्ष्य-आधारित विकास नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्यपाल ने असम के सभी पात्र नागरिकों से 16 अगस्त 2026 तक अपने और अपने परिवार के सदस्यों की स्व-गणना पूरी करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने 17 अगस्त से 15 सितंबर 2026 तक चलने वाली घर-घर गणना के दौरान प्रगणकों को सही एवं पूर्ण जानकारी देकर सहयोग करने की अपील की। उन्होंने लोगों से अपने परिवार, मित्रों, पड़ोसियों और सहकर्मियों को भी जनगणना-2027 में भाग लेने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। इस अवसर पर निदेशक-सह-मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी विश्वजीत पेगू सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

नाजिरा के बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कांग्रेस की विशेष पहल

गुवाहाटी (हिंस)। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नाजिरा के बाढ़ प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के मुख्य आयोजक श्रीनिवास बीवी के नेतृत्व में सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने नेपालीखुटी क्षेत्र में श्रमदान कर घरों, सड़कों और बाढ़ से क्षतिग्रस्त वाहनों से कीचड़ व मलबा हटाया। वहीं, पूर्व सांसद एवं एपीसीसी मीडिया विभाग के सलाहकार अब्दुल खालिक 22 सदस्यीय दल, जिसमें बढ़ई भी शामिल हैं, के साथ नाजिरा पहुंचे। यह टीम 5 अगस्त से बाढ़ में क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत का कार्य शुरू करेगी। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्यों में जुटे हुए हैं।

बोड़ोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीसी) : हग्रामा महिलारी की अध्यक्षता में बोड़ोलैंड विजिलेंस और मॉनिटरिंग कमेटी की पहली संयुक्त बैठक संपन्न

कोकराझाड़(विभास)। बोड़ोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, नवगठित *बोड़ोलैंड विजिलेंस कमेटी* और *बोड़ोलैंड मॉनिटर कमेटी* की पहली संयुक्त बैठक आज कोकराझाड़ के बोडोफा नग्वर स्थित बीटीसी सचिवालय के सम्मेलन हॉल में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता बीटीसी प्रमुख और दोनों समितियों के अध्यक्ष हग्रामा महिलारी ने की। बैठक में समितियों के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे पूर्व विधायक और पूर्व एमसीएलए, वर्तमान एमसीएलए, कार्यकारी सदस्य मृत्युंजय नार्जारी, अपर प्रधान सचिव प्रंजीत वैरी, बीटीसी के वरिष्ठ अधिकारी और दोनों समितियों के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। सदस्यों को संबोधित करते हुए बीटीसी प्रमुख हग्रामा महिलारी ने कहा कि इन समितियों का गठन बीटीसी के अंतर्गत विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार के कार्यक्रमों के तहत

विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही, गुणवत्ता आश्वासन और संस्थागत निगरानी को मजबूत करने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक संसाधनों का सही उपयोग हो और विकास का लाभ समय पर और निष्पक्ष रूप से वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे। मजबूत निगरानी की आवश्यकता पर बल देते हुए बीटीसी प्रमुख ने कहा कि ये समितियां विकासात्मक कार्यों की स्वतंत्र देखरेख और जमीनी स्तर पर समय पर फीडबैक प्रदान करके प्रशासन और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण पुल का काम करेंगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पूरे क्षेत्र में संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए बीटीसी के सभी जिलों और उप-मंडलों की निष्पक्ष और समान रूप से निगरानी की जाएगी। बैठक में बोड़ोलैंड विजिलेंस और मॉनिटरिंग समितियों के अधिकार, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। सुझाव और क्षेत्र निरीक्षण: सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और बहुमूल्य सुझाव दिए। विकास कार्यों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन के लिए नियमित क्षेत्रीय निरीक्षण, व्यवस्थित रिपोर्टिंग और प्रशासन के साथ करीबी तालमेल पर जोर दिया गया। सदस्यों की सराहना: दोनों समितियों के सदस्यों ने बीटीसी प्रमुख हग्रामा महिलारी की इस पहल की सराहना की और इसे बीटीसी प्रशासन में पारदर्शिता और सुशासन को सुदृढ़ करने के लिए एक समय पर उठाया गया प्रगतिशील कदम बताया। सदस्यों ने माना कि ये समितियां लोगों के अधिकारों, पहचान और हितों की रक्षा करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी कि सरकारी योजनाएं और विकास कार्यक्रम प्रभावी ढंग से और अपने निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप लागू हों।

मारवाड़ी पंचायत लंका की बड़ी पहल : ऊपरी असम के बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाई जाएगी राहत सामग्री

होजाई (निसं)। असम में भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए सामाजिक संस्थाएं लगातार आगे आ रही हैं। इसी क्रम में होजाई जिले के लंका स्थित मारवाड़ी पंचायत, लंका ने एक सराहनीय सामाजिक पहल करते हुए ऊपरी असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। बाढ़ के कारण बेघर और प्रभावित हुए परिवारों की दिनचर्या को पटरी पर लाने के उद्देश्य से इस अभियान के तहत 200 से अधिक बर्तन सेट जिसमें-दो थाली, दो गिलास, दो प्लेट, एक डेकची, एक कड़ाई, एक बड़ी चम्मच, एक छोटी चम्मच सहित पूरा एक सेट बनाया गया। बाढ़ के पानी में जिन लोगों के घर का सामान और रसोई बह गई है, उनके लिए यह मदद काफी राहत देने वाली साबित होगी। इस पुण्य कार्य और राहत अभियान को सफल बनाने में स्थानीय समाजसेवियों का विशेष योगदान रहा है। इस पूरी मुहिम में मुख्य रूप से समाजसेवी रोहित अग्रवाला, पंकज बजाज, बिनोद शर्मा, अशोक

कामदार, संदीप अग्रवाल, अमित अग्रवाल, पवन कामदार, अमन मुंदड़ा, पंकज प्रजापत और अंकित रांका सक्रिय रूप से शामिल हैं। मारवाड़ी पंचायत लंका के प्रतिनिधियों का कहना है कि संकट की इस घड़ी में बाढ़ पीड़ितों की सहायता करना उनका प्राथमिक कर्तव्य है और उसी कड़ी में यह एक छोटा सा प्रयास है व आने वाले दिनों में भी आवश्यकतानुसार राहत कार्य जारी रखे जाएंगे।

संपादकीय

संसद में 'भगवा' स्वांग

संसद भवन कोई नाटक खेलने या स्वांग रचने का मंच नहीं है। वह देश के गणतंत्र का सर्वोच्च, पवित्र, गरिमामय और मर्यादित मंच है। बेशक हमारे माननीय सांसदों ने ही इसकी गरिमा, छवि सवालिया की है। बेशक संसद परिसर में सांसद और राजनीतिक समूह विरोध-प्रदर्शन कर सकते हैं, धरने भी दिए जाते रहे हैं, लेकिन ऐसे ढोंग, नौटंकी पर उन्हें ही विचार करना चाहिए कि ये देशहित, जनहित और असंख्य आस्थाओं के पक्ष में है अथवा नहीं! बिहार से निर्दलीय सांसद (कांग्रेस समर्थक) पप्पू यादव ने संसद परिसर में जो कुछ भी किया, निश्चित रूप से वह सनातन-विरोधी था। प्रभु श्रीराम का अपमान भी था। मिथ्या, खोखले आरोपों का नाटकीय मंचन भी था। पप्पू यादव संसद भवन को 'राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय' का प्रतीक भी नहीं दे सकते। साधु-संतों ने अयोध्या के राम मंदिर में चंदा-चढ़ावे की चोरी-डकैती की, ऐसा कोई साक्ष्य, आरोप या जांच-दल का निष्कर्ष नहीं है। इस मुद्दे पर संसद के भीतर विचारोत्तेजक, आरोपिया बहस की जानी चाहिए और मोदी सरकार-भाजपा को जवाब देने को बाध्य किया जाना चाहिए। पप्पू यादव का साधु-वेश धारण करना और चंदा-चोरी का प्रतीकात्मक अभिनय करना कमोबेश संसद भवन में नहीं किया जाना चाहिए था। पूर्णिया के लाखों लोगों ने उन्हें इसलिए निर्वाचित नहीं किया है। संविधान लागू हुए 76 वर्ष बीत चुके हैं और 18वीं लोकसभा अभी अस्तित्व में है, लेकिन ऐसी अपमानजनक राजनीति का नाटक हमने नहीं सुना और बीते तीन दशकों से देखा भी नहीं है। सचमुच प्रभु श्रीराम के मंदिर में यह चोरी-डकैती अत्यंत नीच, घटिया किस्म का भ्रष्टाचार है। जब चोरी के पैसे से बनाई गई संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए जाएंगे, तो भी राजनीतिक दल चिल्ल-पौं करेंगे। बहरहाल इस संदर्भ में जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी, वह की गई है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बंसल का इस्तीफा मंजूर हो चुका है और नए महासचिव पदासीन हो रहे हैं। जो चेहरे सवालिया और कलंकित हैं, उनसे पुलिस और जांच-दल ने पूछताछ की है। पप्पू ने ऐसे कुछ जिम्मेदार लोगों को 'चोर' कहा है, जो कानूनन उचित नहीं है। जांच अभी जारी है। सर्वोच्च अदालत तक मामला पहुंच चुका है और अदालत ने एसआईटी की रपट का अभी तक का ब्यौरा मांगा है। कई कलंकित, भ्रष्ट चेहरे अब भी जेल में हैं और पुलिस उनसे सिलसिलेवार पूछताछ कर रही है। यकीनन राम मंदिर के भीतर का यह अपराध एक आस्थावान वर्ग के लिए 'आध्यात्मिक आघात' से कम नहीं है। यदि यह अपराध कुछ कुकर्मी न करते, तो यह मुद्दा ही न बनता, सनातन अपमानित न होता और पप्पू यादव जैसे सांसद संसद भवन में ही नाटक न करते, लेकिन अब यह राजनीतिक, चुनावी मुद्दा बना दिया गया है। पप्पू यादव के ड्रामे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, अयोध्या-फैजाबाद के सपा सांसद अवधेश प्रसाद, सपा सांसद डिंपल यादव आदि विपक्ष के कई चेहरे सम्मिलित थे। पप्पू नाटक कर रहे थे और चंदे के रुपए अपनी जेब में डाल रहे थे। चांदी को नाटकीय मंचन किया जा रहा था। उनके सहयोगी सांसदों ने 'प्रतीकात्मक' तौर पर उनकी पिटाई भी की। पप्पू चंदे की पेटी लेकर भागने लगे, तो उनसे वह पेटी छीनने का प्रयास भी किया गया। यकीनन इस नाटक ने कुछ हिंदूवादी संगठनों, साधु-संतों और सांसदों को भी आक्रोशित किया। साधु-संतों ने अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ जैसे शहरों में जुलूस निकाले, पप्पू के स्वांग की भर्त्सना की और प्राथमिकियां दर्ज कराई गईं। इनके नतीजतन पप्पू यादव के सरकारी आवास में घुस कर हमलावरों ने सांसद पर हमला किया। जूते-चप्पल उनकी ओर उछाले और टीवी चैनलों पर एक बड़ा-सा चाकू दिखाया गया। सांसद का कहना था कि हमलावर उन्हें मारने आए थे। आज जनता न होती, तो कुछ भी अनिष्ट हो सकता था। बहरहाल सांसद के समर्थकों ने हमलावर को पकड़ कर खूब धुनाई की। बहरहाल इस संदर्भ में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है, लिहाजा कानूनी कार्रवाई उसी पर छोड़ देनी चाहिए। कुछ टीवी एंकर व्यर्थ में उछल रहे हैं और अपना गला फाड़ रहे हैं। वे देश के कानून नहीं हैं। हमारी बुनियादी चिंता और सरोकार संसद के प्रति है। स्पीकर ने पप्पू यादव के स्वांग की निंदा की है। यही पर्याप्त नहीं है।

संसद परिसर में सांसद और राजनीतिक समूह विरोध-प्रदर्शन कर सकते हैं, धरने भी दिए जाते रहे हैं, लेकिन ऐसे ढोंग, नौटंकी पर उन्हें ही विचार करना चाहिए कि ये देशहित, जनहित और असंख्य आस्थाओं के पक्ष में है अथवा नहीं! बिहार से निर्दलीय सांसद (कांग्रेस समर्थक) पप्पू यादव ने संसद परिसर में जो कुछ भी किया, निश्चित रूप से वह सनातन-विरोधी था। प्रभु श्रीराम का अपमान भी था। मिथ्या, खोखले आरोपों का नाटकीय मंचन भी था। पप्पू यादव संसद भवन को 'राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय' का प्रतीक भी नहीं दे सकते। साधु-संतों ने अयोध्या के राम मंदिर में चंदा-चढ़ावे की चोरी-डकैती की, ऐसा कोई साक्ष्य, आरोप या जांच-दल का निष्कर्ष नहीं है। इस मुद्दे पर संसद के भीतर विचारोत्तेजक, आरोपिया बहस की जानी चाहिए और मोदी सरकार-भाजपा को जवाब देने को बाध्य किया जाना चाहिए। पप्पू यादव का साधु-वेश धारण करना और चंदा-चोरी का प्रतीकात्मक अभिनय करना कमोबेश संसद भवन में नहीं किया जाना चाहिए था। पूर्णिया के लाखों लोगों ने उन्हें इसलिए निर्वाचित नहीं किया है।

कुछ अलग

पूर्णता और दरार

प्रकृति अपने आप में पूर्ण होते हुए भी कभी अपने किसी कार्य को पूर्णता प्रदान नहीं करती। उसने कभी पूर्ण वृक्ष नहीं बनाए। पूर्ण पर्वत नहीं बनाए। पूर्ण समुद्र नहीं बनाए। यहां तक कि पूर्ण ऋतुएं भी नहीं। हर ऋतु अपने भीतर अगली ऋतु का बीज छिपाकर चलती है। काल आगे बढ़ता है। पहाड़ बूढ़े होते हैं। नदियां अपने मार्ग बदलने के बावजूद सफर जारी रखती हैं। महाद्वीप टूटते हैं, जुड़ते हैं। हिमयुग आया। पिघला। स्मृति बन गया। वन उगे। सूखे। फिर उग आए। आकाश बदलता रहा। समुद्र बदलते रहे। केवल परिवर्तन अपरिवर्तनीय रहा। काल ने पहली बार समझा कि सृष्टि किसी भवन की तरह निर्मित नहीं हुई। वह किसी कविता की तरह लिखी गई है। और कविता कभी अंतिम नहीं होती। दार्शनिक कहते हैं- पूर्णता मनुष्य की सबसे पुरानी आकांक्षा है। प्रकृति की नहीं। प्रकृति केवल संतुलन चाहती है। संतुलन और पूर्णता में वही अंतर है जो श्वास और मूर्ति में होता है। मूर्ति पूर्ण दिखाई देती है। श्वास अपूर्ण। किन्तु जीवन हमेशा श्वास में बसता है। मूर्ति में नहीं। कई युगान्तरों के बाद मनुष्य ने इस कथा को अनेक रूपों में बुना, गाया और सुना। कहीं यह मिथक बनी। कहीं दर्शन। कहीं कविता। कहीं केवल एक लोककथा। किन्तु हर रूप में एक बात समान रही- पहली दरार किसी पत्थर की कमजोरी नहीं थी। वह सृष्टि की विनम्रता थी। वजह साफ थी कि जो स्वयं को पूर्ण मान लेता है, उसके भीतर परिवर्तन मर जाता है। और जहां परिवर्तन समाप्त होता है, वहां जीवन जीवन नहीं रहता। केवल स्मृति बनकर रह जाता है। काल ने उस दिन अपनी पहली टिप्पणी लिखी। किसी पत्थर पर नहीं। किसी पुस्तक में भी नहीं।

राष्ट्रमंडल खेल 2026: चुनौतियों के बीच चमका भारत

राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की नई उड़ान

राष्ट्रमंडल खेल केवल पदकों की प्रतियोगिता नहीं बल्कि किसी देश की खेल संस्कृति, प्रतिभा विकास, खेल विज्ञान, प्रशिक्षण व्यवस्था और दीर्घकालिक खेल नीति का दर्पण भी होते हैं। ग्लासगो (स्कॉटलैंड) में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों का समापन भारत के लिए अनेक उपलब्धियों, कुछ अधूरी अपेक्षाओं और भविष्य की नई संभावनाओं के साथ हुआ। भारतीय दल ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार प्रतियोगिता के कार्यक्रम में निशानेबाजी, कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस इत्यादि भारत के कई पारंपरिक मजबूत खेल शामिल ही नहीं थे। इन खेलों में भारत सामान्यतः बड़ी संख्या में पदक जीतता रहा है। ऐसे में सीमित अवसरों के बावजूद चौथा स्थान बनाए रखना भारतीय खिलाड़ियों की क्षमता और जुझारूपन का प्रमाण है। पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया ने 70 स्वर्ण सहित कुल 171 पदक जीतकर एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा। इंग्लैंड 110 पदकों के साथ दूसरे तथा कनाडा 62 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। मेजबान स्कॉटलैंड भी 39 पदकों के साथ प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए पांचवें स्थान पर रहा। भारत और स्कॉटलैंड के कुल पदक समान रहे लेकिन स्वर्ण पदकों की संख्या के आधार पर भारत चौथे स्थान पर रहा।

यदि पिछले राष्ट्रमंडल खेलों के प्रदर्शन की तुलना करें तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। वर्ष 2018 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य सहित कुल 66 पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया था। उस प्रतियोगिता में निशानेबाजी ने अकेले 16 पदक दिलाकर भारत की सफलता में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और कुश्ती में भी भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था। 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य सहित कुल 61 पदक जीतकर चौथा स्थान प्राप्त किया था। तब कुश्ती में भारत के सभी 12 पहलवानों ने पदक जीतकर इतिहास रचा था जबकि भारोत्तोलन और टेबल टेनिस में भी भारतीय खिलाड़ियों ने उल्लेखनीय सफलता अर्जित की थी। इन दोनों आयोजनों की तुलना में 2026 के ग्लासगो खेलों में भारत के कुल पदकों की संख्या घटकर 39 रह गई। पहली दृष्टि में यह गिरावट चिंताजनक लग सकती है किंतु यदि प्रतियोगिता के कार्यक्रम का विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होता है कि भारत के अनेक पदक संभावित खेल इस बार आयोजित ही नहीं किए गए। इसलिए केवल पदकों की संख्या के आधार पर प्रदर्शन का मूल्यांकन करना उचित नहीं होगा। वास्तव में भारत ने उपलब्ध अवसरों का काफी प्रभावी उपयोग किया और जिन खेलों में उसने भाग लिया, उनमें उल्लेखनीय सफलता अर्जित की। इस बार भारतीय मुक्केबाजों ने

भारतीय दल ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार प्रतियोगिता के कार्यक्रम में निशानेबाजी, कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस इत्यादि भारत के कई पारंपरिक मजबूत खेल शामिल ही नहीं थे। इन खेलों में भारत सामान्यतः बड़ी संख्या में पदक जीतता रहा है। ऐसे में सीमित अवसरों के बावजूद चौथा स्थान बनाए रखना भारतीय खिलाड़ियों की क्षमता और जुझारूपन का प्रमाण है। पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया ने 70 स्वर्ण सहित कुल 171 पदक जीतकर एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा। इंग्लैंड 110 पदकों के साथ दूसरे तथा कनाडा 62 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। मेजबान स्कॉटलैंड भी 39 पदकों के साथ प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए पांचवें स्थान पर रहा। भारत और स्कॉटलैंड के कुल पदक समान रहे लेकिन स्वर्ण पदकों की संख्या के आधार पर भारत चौथे स्थान पर रहा।

राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ अभियान चलाया। भारत ने मुक्केबाजी में सात स्वर्ण और तीन रजत सहित कुल दस पदक जीतकर नया इतिहास रच दिया। महिला मुक्केबाजों ने विशेष रूप से प्रभावित किया। जैस्मीन लम्बोरिया, प्रिया घनघस, साक्षी चौधरी और प्रीति पवार जैसी युवा खिलाड़ियों ने यह संकेत दिया कि भारतीय महिला मुक्केबाजी का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है। ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन स्वर्ण से भले चूक गई लेकिन उनका अनुभव और प्रदर्शन भारतीय मुक्केबाजी की मजबूती का प्रमाण बना रहा। पुरुष वर्ग में भी सचिन सिवाच और अंकुश सहित अन्य मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की पदक संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह सफलता दर्शाती है कि भारतीय मुक्केबाजी अब केवल कुछ खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं रही बल्कि उसके पास प्रतिभाओं की व्यापक श्रृंखला तैयार हो चुकी है। भारोत्तोलन ने भी भारत की प्रतिष्ठा बनाए रखी। पिछले एक दशक में इस खेल में भारतीय खिलाड़ियों ने निरंतर प्रगति की है। ग्लासगो में भी उन्होंने अपने प्रदर्शन से यह साबित किया कि विश्व स्तर पर भारत अब एक मजबूत शक्ति बन चुका है। जूडो में भारतीय खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया और कई महत्वपूर्ण पदक जीतकर यह संदेश दिया कि यह खेल भी भारत में तेजी से विकसित हो रहा है। हालांकि जूडो खिलाड़ी तूलिका मान का डोपिंग रोधी नियमों के अंतर्गत तीन बार 'वेयरअबाउट्स' संबंधी जानकारी देने में विफल रहने के कारण अस्थायी निलंबन और प्रतियोगिता से बाहर होना भारतीय दल के लिए एक बड़ा झटका था। यह घटना बताती है कि विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा में केवल खेल कौशल ही नहीं, डोपिंग रोधी नियमों के प्रति पूर्ण जागरूकता और अनुशासन भी उतना ही आवश्यक है। एथलेटिक्स में भारत का प्रदर्शन इस बार विशेष चर्चा का विषय रहा। गुलवीर सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में नया अध्याय जोड़ते हुए 10,000 मीटर दौड़ में रजत और 5,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वे एक ही राष्ट्रमंडल खेल में ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धाओं में दो पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। इससे पहले भारत को इन लंबी दूरी की स्पर्धाओं में कभी पदक नहीं मिला था। यह उपलब्धि भारतीय एथलेटिक्स के बदलते स्वरूप और वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रणाली की सफलता का संकेत देती है। पैरा खेलों में भी भारत ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल सात पदक जीतकर नया इतिहास बनाया। यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा वर्ग में भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बराबर है। यदि भारतीय दल के प्रदर्शन का गहन विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होता है कि इस बार महिलाओं ने शानदार योगदान दिया। महिला खिलाड़ियों ने 8 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीतकर भारतीय खेलों में बढ़ती महिला भागीदारी और उत्कृष्टता का परिचय दिया। दूसरी ओर पुरुष खिलाड़ियों ने कुल 23 पदक जीतकर संतुलित प्रदर्शन किया। फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि 2026 का प्रदर्शन भारत के लिए संतोषजनक अवश्य है लेकिन ऐतिहासिक नहीं। वर्ष 2010 के नई दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल आज भी भारत के स्वर्णिम अध्याय बने हुए हैं, जब भारत ने 38 स्वर्ण सहित कुल 101 पदक जीतकर ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया था। घरेलू मैदान का लाभ अपनी जगह है लेकिन वह प्रदर्शन यह भी दर्शाता है कि यदि मजबूत खेल अवसंरचना, व्यापक खिलाड़ी आधार और सुव्यवस्थित तैयारी हो तो भारत शीर्ष देशों को कड़ी चुनौती देने की क्षमता रखता है। भारत की खेल यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष अब यह है कि देश अब कुछ चुनिंदा खेलों तक सीमित नहीं रह गया है। पहले भारत की अधिकांश सफलता निशानेबाजी, कुश्ती, बैडमिंटन और भारोत्तोलन तक सीमित रहती थी जबकि अब मुक्केबाजी, जूडो, एथलेटिक्स और पैरा खेलों में भी लगातार नए खिलाड़ी उभर रहे हैं। यह परिवर्तन भारत की खेल नीति, खेलो इंडिया जैसी योजनाओं, बेहतर प्रशिक्षण सुविधाओं, खेल विज्ञान, पोषण और खिलाड़ियों को मिलने वाले आर्थिक सहयोग का सकारात्मक परिणाम है। हालांकि अभी भी प्रतिभा पहचान, जमीनी स्तर पर कोचिंग, खेल चिकित्सा, मानसिक प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिस्पर्धी अनुभव को और मजबूत करने की आवश्यकता बनी हुई है। अब भारतीय खेल जगत की निगाहें वर्ष 2030 पर टिक गई हैं, जब राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। यह केवल एक खेल आयोजन नहीं बल्कि भारत के लिए विश्व के सामने अपनी खेल क्षमता, आधुनिक अवसंरचना और संगठनात्मक दक्षता प्रदर्शित करने का सुनहरा अवसर होगा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों ने भारत को यह विश्वास अवश्य दिलाया है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हों, भारतीय खिलाड़ी हर मंच पर देश का गौरव बढ़ाने का सामर्थ्य रखते हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि इन उपलब्धियों को अंतिम लक्ष्य न मानकर उन्हें ओलंपिक और वैश्विक खेल महाशक्ति बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जाए। जिन खेलों में भारत विश्वस्तरीय शक्ति बन चुका है, उन्हें और सशक्त किया जाए तथा एथलेटिक्स, तैराकी, जिम्नास्टिक और अन्य ओलंपिक खेलों में भी दीर्घकालिक निवेश बढ़ाया जाए।

देश दुनीया से

अब जेनेरिक दवाओं संबंधी नई चिंताएं

एक अगस्त से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका में आयातित जेनेरिक दवाओं पर चरणबद्ध तरीके से टैरिफ (आयात शुल्क) लगाने संबंधी नीति लागू की गई है। इस नीति के तहत 1 अगस्त 2026 से 31 जुलाई 2028 तक, यानी शुरुआती दो वर्षों के लिए, आयातित जेनेरिक दवाओं को टैरिफ से पूरी तरह मुक्त रखा गया है, ताकि अमेरिकी बाजार में दवा आपूर्ति में तुरंत कोई बाधा न आए। इसके पश्चात, 1 अगस्त 2028 से 31 जुलाई 2029 तक एक वर्ष के लिए दवाओं के मूल्य पर सीधे 100 प्रतिशत का टैरिफ लागू किया जाएगा। अंततः 1 अगस्त 2029 के बाद इस टैरिफ को बढ़ाकर 200 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि ट्रंप द्वारा जेनेरिक दवाओं पर इस कड़े टैरिफ ढांचे को लागू करने का मुख्य उद्देश्य विदेशी दवा कंपनियों को अमेरिका के भीतर निर्माण इकाइयां (मैन्युफैक्चरिंग प्लांट) स्थापित करने के लिए बाध्य करना है। जो दवा निर्माता दी गई इस समयावधि के भीतर अपना उत्पादन घरेलू स्तर पर अमेरिका में स्थानांतरित नहीं करेंगे, उन पर 200 प्रतिशत का भारी आर्थिक दंडस्वरूप टैरिफ लागू होगा। चूंकि भारतीय दवा उद्योग अमेरिकी बाजार का एक मुख्य आपूर्तिकर्ता है, इसलिए भारत पर इसका गहरा प्रभाव पडना स्वाभाविक है। ज्ञातव्य है कि पिछले वर्ष 26 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रांडेड या पेटेंटेड दवाओं पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिसे 1 अक्टूबर 2025 से लागू किया गया। ट्रंप के दवा टैरिफ के उस निर्णय का भारतीय फार्मा कंपनियों पर विशेष असर नहीं हुआ था। इसका प्रमुख कारण यह था कि भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाली कुल दवाओं में पेटेंट या ब्रांडेड दवाओं का हिस्सा महज 5 प्रतिशत ही है। यह दवा टैरिफ उन कंपनियों पर लागू नहीं हुआ जो अमेरिका के भीतर ही दवा बनाने के लिए अपना प्लांट लगा रही हैं। ट्रंप ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि यदि किसी फार्मा कंपनी की रुचि अमेरिका में दवाओं के विनिर्माण में है या किसी कंपनी ने अमेरिका में अपना प्लांट लगाना शुरू

कर दिया है, तो उसे टैरिफ से पूर्ण छूट मिलेगी। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया की बड़ी फार्मा कंपनियों को अमेरिकी भूमि पर उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना है। इस फैसले का सबसे अधिक प्रभाव उन देशों पर पड़ा जिनकी फार्मा कंपनियां अमेरिका को बड़े पैमाने पर ब्रांडेड दवाओं का निर्यात करती हैं, जिनमें आयरलैंड, जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे देश प्रमुख हैं। यहां ब्रांडेड या पेटेंटेड दवाओं और जेनेरिक दवाओं के बीच का अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है। ब्रांडेड दवाएं, यह मूल दवाएं होती हैं जिनकी खोज किसी फार्मा कंपनी ने लंबे शोध और अनुसंधान के बाद की होती है। इसे बनाने वाली कंपनी को एक तय अवधि (जो आमतौर पर 20 साल की होती है) के लिए एकाधिकार या पेटेंट अधिकार मिल जाता है। इस दौरान कोई भी दूसरी कंपनी उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके दवा नहीं बना सकती। जेनेरिक दवाएं, वे दवाएं होती हैं जो ब्रांडेड दवा का पेटेंट समाप्त होने के बाद बाजार में आती हैं। इन्हें ब्रांडेड दवा के समान फॉर्मूले का उपयोग करके ही बनाया जाता है। चूंकि जेनेरिक दवाओं का कोई नया पेटेंट नहीं होता और यह पूर्व-मौजूद फॉर्मूले पर आधारित होती हैं, इसलिए कंपनियों को शोध पर भारी-भरकम खर्च नहीं करना पड़ता। यही कारण है कि जेनेरिक दवाओं की कीमत ब्रांडेड दवाओं की तुलना में बेहद कम होती है। विशेष बात यह है कि भारत अमेरिका को जेनेरिक दवाएं निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है। वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका को लगभग 10 अरब डॉलर की दवाइयां भेजीं, जो भारत के कुल वैश्विक दवा निर्यात का करीब एक-तिहाई से अधिक है। निश्चित रूप से, ट्रंप ने ब्रांडेड दवाओं के बाद अब जेनेरिक दवाओं पर भी टैरिफ लगाने का फैसला अमेरिका में घरेलू दवा उत्पादन को बढ़ाने के लिए लिया है। ट्रंप का यह कदम 'अमेरिका फर्स्ट' और 'मेक इन अमेरिका' की नीति का ही एक हिस्सा है। ट्रंप का यह भी मानना है कि दवाओं के लिए दूसरे देशों पर अत्यधिक निर्भर रहना अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। कोरोना महामारी के दौरान अमेरिका ने यह अनुभव किया है कि यदि दवाइयों की वैश्विक सप्लाई चेन टूटती है, तो देश में दवाओं की भीषण किल्लत हो सकती है। ऐसे में ट्रंप ने यह कदम अमेरिका की पूरी फार्मा सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से उठाया है। ट्रंप द्वारा जेनेरिक दवाओं पर तुरंत टैरिफ न लगाकर दो वर्ष की छूट देने के पीछे कुछ विशेष कारण भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका में डॉक्टर मरीजों के लिए जो प्रिसक्रिप्शन लिखते हैं, उनमें से हर 10 में से करीब 4 दवाएं भारतीय कंपनियों द्वारा निर्मित जेनेरिक दवाएं होती हैं। जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं से 80 से 90 प्रतिशत तक सस्ती होती हैं। यदि जेनेरिक दवाओं पर तुरंत 100 प्रतिशत या 200 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया जाता, तो अमेरिका में दवाओं की कीमतें रातों-रात आसमान छूने लगतीं। इससे आम अमेरिकी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं अत्यधिक महंगी हो जातीं, जो सीधे तौर पर ट्रंप सरकार के लिए घरेलू असंतोष का कारण बन सकता था। वास्तव में, सस्ती भारतीय जेनेरिक दवाएं अमेरिकी अर्थव्यवस्था और वहां के स्वास्थ्य तंत्र के लिए लागत-बचत का एक प्रमुख जरिया हैं।

आप का नजरीया

भाजपा को झटका

विधानसभा के हालिया उपचुनावों के जो परिणाम सामने आए हैं, वे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के माथे पर शिकन लाने वाले कहे जा सकते हैं। बिहार जहां भाजपा के नेतृत्व में गठबंधन सरकार है और पहली बार उसका मुख्यमंत्री बना है, वहां हाईप्रोफाइल बांकीपुर उपचुनाव में उसे हार का सामना करना पड़े तो इसको लेकर पार्टी की फिक्र बढ़ना लाजमी ही है। पिछले बिहार विधानसभा चुनावों में नई-नवेली बनी जन सुराज पार्टी यानी जे.एस.पी की करारी हार हुई थी। उस हार से सबक लेकर जेएसपी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ताल ठोककर बांकीपुर उपचुनाव मैदान में उतरे थे। इस तरह प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में अच्छी जीत हासिल करके भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाबी हासिल कर ही ली। राज्य में सत्ताधारी गठबंधन का नेतृत्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिये चुनाव परिणाम और भी अधिक कष्टदायक होगा, क्योंकि यह पार्टी के खाते वाली सीट थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन के राज्यसभा के लिये चुने जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। जाहिर तौर पर यह सामान्य विधानसभा सीट नहीं थी, इसको फिर से हासिल करना भाजपा की प्राथमिकता भी रही होगी। कमोबेश भाजपा के लिये ऐसी ही निराशाजनक खबरें अन्य राज्यों से भी आई हैं। लंबे समय से भाजपा का गढ़ माने जाने वाले एक और राज्य मध्यप्रदेश में भाजपा उम्मीदवार को हार मिली। मध्य प्रदेश की दतिया सीट कांग्रेस ने कब्जा ली है। दरअसल, इस सीट में उपचुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर खासा बवाल हुआ था। पिछली भाजपा सरकार में इस सीट से एक दिग्गज मंत्री बने थे। इस बार उनको टिकट न मिलने पर उग्र प्रदर्शन व धरने हुए थे। इस बड़े विवाद का फायदा कांग्रेस के प्रत्याशी को हुआ। हां, भाजपा के लिए एक सुकूनभरी खबर गुजरात से आई। पार्टी के इस परंपरागत गढ़ में उपचुनाव के बाद, वडोदरा जिले की मंजलपुर विधानसभा सीट पर पार्टी ने अपना कब्जा बरकरार रखा। बहरहाल, बिहार में बांकीपुर सीट को खो देना भाजपा को परेशान करने वाला जरूर है। बांकीपुर का बदला जनादेश न सिर्फ नितिन नवीन के लिये, बल्कि बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिये भी असहज करने वाली स्थिति है। दरअसल, प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने स्थानीय मुद्दों के साथ मुख्यमंत्री पर तीखे हमले किये थे। उन्होंने राज्य में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कानून-व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों को लगातार विभिन्न मंचों से उठाया था। जाहिर है अब मुख्यमंत्री को पार्टी के भीतर ही जवाबदेही को लेकर मुश्किल स्थिति का सामना करना होगा। वहीं इस जीत से प्रशांत किशोर के हौसले बुलंद हैं। वह देश के कई दिग्गज राजनेताओं के चुनाव अभियानों के सारथी रह चुके हैं। वे जनता के मिजाज को भांपने का हुनर भी जानते हैं। अब अपनी जीत से उत्साहित प्रशांत किशोर राज्य सरकार के खिलाफ अपना रुख और सख्त करेंगे। वे आने वाले समय में बिहार में जन सुराज पार्टी को तीसरे मोर्चे के तौर पर पेश करने की तैयारी में हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच असहज होता गठबंधन, पहले ही प्रशांत किशोर के लिये अनुकूल स्थितियां बना रहा है। राजनीतिक पंडित इन उपचुनावों के परिणामों की अलग-अलग तरह से व्याख्या कर रहे हैं। दरअसल, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की एक-एक विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव, नीट पेपर लीक और दूसरे मुद्दों को लेकर भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ जेन-जी के विरोध प्रदर्शनों के बाद पहली चुनावी लड़ाई थी।

पिछले बिहार विधानसभा चुनावों में नई-नवेली बनी जन सुराज पार्टी यानी जे.एस.पी की करारी हार हुई थी। उस हार से सबक लेकर जेएसपी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ताल ठोककर बांकीपुर उपचुनाव मैदान में उतरे थे। इस तरह प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में अच्छी जीत हासिल करके भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाबी हासिल कर ही ली। राज्य में सत्ताधारी गठबंधन का नेतृत्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिये चुनाव परिणाम और भी अधिक कष्टदायक होगा, क्योंकि यह पार्टी के खाते वाली सीट थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन के राज्यसभा के लिये चुने जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। जाहिर तौर पर यह सामान्य विधानसभा सीट नहीं थी, इसको फिर से हासिल करना भाजपा की प्राथमिकता भी रही होगी। कमोबेश भाजपा के लिये ऐसी ही निराशाजनक खबरें अन्य राज्यों से भी आई हैं। लंबे समय से भाजपा का गढ़ माने जाने वाले एक और राज्य मध्यप्रदेश में भाजपा उम्मीदवार को हार मिली। मध्य प्रदेश की दतिया सीट कांग्रेस ने कब्जा ली है। दरअसल, इस सीट में उपचुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर खासा बवाल हुआ था। पिछली भाजपा सरकार में इस सीट से एक दिग्गज मंत्री बने थे। इस बार उनको टिकट न मिलने पर उग्र प्रदर्शन व धरने हुए थे। इस बड़े विवाद का फायदा कांग्रेस के प्रत्याशी को हुआ। हां, भाजपा के लिए एक सुकूनभरी खबर गुजरात से आई। पार्टी के इस परंपरागत गढ़ में उपचुनाव के बाद, वडोदरा जिले की मंजलपुर विधानसभा सीट पर पार्टी ने अपना कब्जा बरकरार रखा।

दृष्टि कोण

त्यागपत्र : खुशी मनाने का सबब

कुछ दिन पहले ही एक खबर, जिसे अत्यंत नकारात्मक तरीके से देखा जा रहा था, यह थी कि भारत के एक गौरवपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (इसरो) के 100 से अधिक वैज्ञानिकों ने या तो संस्थान से त्यागपत्र दे दिया है अथवा समय से पूर्व सेवानिवृत्ति ले ली है। इस खबर से ऐसा लग रहा था कि शायद भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को इससे एक बड़ा झटका मिल सकता है। लेकिन वहीं एक निजी कंपनी द्वारा बिना कोई असफलता झेले अंतरिक्ष में अपना रॉकेट लॉन्च करने के बाद यह बात स्पष्ट हो रही है कि चाहे इसरो के वैज्ञानिक संस्थान से तो अलग हो रहे हैं, लेकिन वे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से अलग नहीं हो रहे, बल्कि एक अन्य प्रकार से अपना जुड़ाव मजबूती से बनाए हुए हैं, और निजी क्षेत्र के माध्यम से देश के लिए सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। जुलाई 18, 2026 को भारत की एक निजी अंतरिक्ष स्पेस कंपनी 'स्काईरूट एरोस्पेस' ने सफलतापूर्वक विक्रम-1 नाम के रॉकेट को लॉन्च करके इतिहास रच दिया। अब भारत अमरीका, चीन और जापान के बाद चौथा ऐसा देश बन गया है जिसकी किसी निजी कंपनी ने अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने में सफलता पाई है। विक्रम-1 की सफलता की खास बात यह है कि जहां बाकी देशों की निजी कंपनियों ने एक या एक से अधिक बार असफलता झेलने के बाद सफल लॉन्च कर पाई, स्काईरूट ने यह काम पहले ही प्रयास में कर दिया है। प्रारंभ में अत्यंत सामान्य शुरुआत से आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार इसरो ने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए, उससे इस क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा की उत्कृष्टता विश्व में स्थापित हुई है। पीएसएलवी, मंगलयान, चंद्रयान और भविष्य में मानव को अंतरिक्ष में ले जाने की तैयारी के साथ पूर्णतया स्वदेशी गगनयान मिशन, नैविक (पूर्णतया स्वदेशी नेवीगेशन) और कृषि, आपदा प्रबंधन, जल संसाधन, शहरी नियोजन, मौसम पूर्वानुमान, और मत्सयन के लिए विश्व की सबसे बड़ी रिमोट सेंसिंग सेटेलाईट बनाने सहित इसरो की तमाम उपलब्धियों के

बाद भारत सरकार द्वारा ही यह सोचा समझा निर्णय लिया गया कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए। प्रारंभ में जब भारत के पास अंतरिक्ष क्षमता नहीं थी और दुनिया के विकसित देश हमसे कहीं आगे थे, सरकारी मदद के बिना अंतरिक्ष क्षेत्र में आगे बढ़ना इसलिए संभव नहीं था, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश अपनी प्रौद्योगिकी भारत से साझा करने के लिए तैयार नहीं था। सरकारी मदद और हमारे वैज्ञानिकों की सूझबूझ और मेहनत से इसरो ने विभिन्न उपलब्धियों के माध्यम से देश का मस्तक ऊंचा किया। लेकिन अब यह महसूस किया जा रहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के व्यवसायीकरण की अपार संभावनाएं हैं। पूर्व में भी जन संचार, मौसम विज्ञान एवं विभिन्न प्रकार के शोध में इसरो ने काफी काम किया है, लेकिन स्पेस एक्स एक्सिऑम, स्पेस, सेयरा स्पेस, एस्ट्रो कॉल, डी ऑरबिट सहित विश्व की कई निजी कंपनियों ने अपने व्यवसाय का विस्तार करते हुए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दिया है। यही नहीं इन कंपनियों का पूंजीगत मूल्यांकन उच्च स्तर पर हो रहा है। अकेले ऐलन मस्क की अमरीकी कंपनी 'स्पेस-एक्स' का पूंजीगत मूल्यांकन 1.6 खरब डालर तक पहुंच चुका है, जो भारत की जीडीपी का लगभग 38 प्रतिशत है। ऐसे में इन बड़ी स्पेस कंपनियों को टक्कर देने हेतु भारत को भी अपनी तैयारी करनी होगी। भारत में 'स्टार्टअप इको सिस्टम' ने पिछले लगभग 12 सालों में खासी तेजी से प्रगति की है, और इसी क्रम में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी नए स्टार्टअप उभरे हैं।

भाजपा प्रदेश कार्यालय में रोजाना होगी जनसुनवाई, पदाधिकारियों की लगाई ड्यूटी तय

गुरुग्राम (हिंस)। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा ने पार्टी कार्यकर्ताओं एवं आमजन की समस्याओं के नियमित निवारण तथा संगठन और जनता के बीच निरंतर संवाद को मजबूत करने की दिशा में पहल की है। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता के निर्देशानुसार पंचकूला स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय पंचकमल में प्रतिदिन एक प्रदेश उपाध्यक्ष अथवा प्रदेश मंत्री की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। प्रदेश कार्यालय की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार छह अगस्त से 22 अगस्त तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक निर्धारित पदाधिकारी प्रदेश कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी तथा आमजन अपनी सामाजिक, स्थानीय एवं संगठनात्मक समस्याओं को लेकर संबंधित पदाधिकारी से मुलाकात कर सकेंगे। भाजपा की इस व्यवस्था का उद्देश्य कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनना, जनसरोकारों से जुड़े विषयों को समझना तथा संबंधित स्तर पर उनके समाधान के लिए आवश्यक समन्वय करना है। इससे प्रदेश कार्यालय में आने वाले कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों को अपनी बात रखने के लिए नियमित मंच उपलब्ध होगा। जारी कार्यक्रम के अनुसार छह अगस्त को प्रदेश मंत्री रवि बतान, सात अगस्त को प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक गुर्जर, आठ अगस्त को प्रदेश मंत्री मीना चौहान, नौ अगस्त को प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक दीपक मंगला, तथा 10 अगस्त को प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक लतिका शर्मा जनसुनवाई के लिए प्रदेश कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।

पंजाब विधानसभा में ई-20 फ्यूल ब्लेंडिंग पॉलिसी के विरोध में प्रस्ताव पारित

उपभोक्ताओं को पेट्रोल व ई-20 में से कोई एक चुनने का मिले विकल्प

चंडीगढ़ (हिंस)। पंजाब विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को राज्य की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने केंद्र की अनिवार्य ई-20 फ्यूल ब्लेंडिंग पॉलिसी के विरोध में प्रस्ताव पारित कर दिया। अब यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को भेजा जाएगा। कांग्रेस के विधायक आज दूसरे दिन भी काले पटके पहनकर सदन में पहुंचे। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने सदन में प्रस्ताव पेश करते हुए आरोप लगाया कि यह पॉलिसी ग्लोबल इथेनॉल-उत्पादक कंपनियों के दबाव में लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह पंजाब के लिए नुकसानदेह होगा, जो पहले से ही गिरते भूजल स्तर के कारण पर्यावरणीय संकट का सामना कर रहा है। चीमा ने कहा कि पॉलिसी को मंजूरी देने से पहले राज्यों से सलाह ली जानी चाहिए थी। उन्होंने यह भी कहा कि उपभोक्ताओं के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस विधायक अवतार हेनरी जूनियर ने दावा किया कि इथेनॉल उत्पादन से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 10,800 लीटर पानी की जरूरत होती है। इस प्रस्ताव पर चर्चा को एक दिन के लिए टाल दिया जाए, ताकि हमें इस मुद्दे का अध्ययन करने और फिर यहां चर्चा करने के लिए कुछ समय मिल सके। कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह ने इस मुद्दे पर सदन में तथ्य पेश करने की बात की। स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने चर्चा को टालने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि पंजाब में इस समय एक करोड़ 25 लाख 88 हजार 551 पंजीकृत वाहन हैं। इन वाहनों पर संकट पैदा हो गया है। इस मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से राणा गुरजीत सिंह, अवतार सिंह जूनियर, परगट सिंह, कैबिनेट मंत्री तरूणप्रीत सिंह सोंद, डॉ.रवजोत सिंह, अमन अरोड़ा, डॉ.बलबीर सिंह द्वारा अपने-अपने तर्क पेश किए गए। प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना किसी अध्ययन के यह फैसला थोपा है। इसे लेकर देश में रोष व्याप्त है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भारत-अमेरिका ट्रेड डील का बड़ा हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बताए कि किस दबाव में यह फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आज पारित हुए प्रस्ताव के संबंध में पंजाब सरकार का पक्ष गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री तथा पैट्रोलियम मंत्री को भेजा जाएगा। सदन की कार्यवाही के दौरान सभी पक्षों की राय के बाद स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने प्रस्ताव पर वोटिंग करवाई, जिसे बहुसम्मति से पारित कर दिया गया।

पंजाब में पीएसआईईसी के पूर्व अधिकारियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

मोहाली और अमृतसर में औद्योगिक भूखंडों के कथित फर्जी आवंटन की जांच तेज

चंडीगढ़ (हिंस)। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को पंजाब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन (पीएसआईईसी) के एक पूर्व मुख्य महाप्रबंधक, एक कार्यकारी निदेशक और एक पूर्व महाप्रबंधक के आवास पर छापेमारी की। केंद्रीय जांच एजेंसी ने निगम के मुख्य कार्यालय से भी मामले से संबंधित रिकॉर्ड मांगा है। सूत्रों के अनुसार ईडी वर्ष 2012 से मोहाली और अमृतसर में कम से कम 20 औद्योगिक भूखंडों के कथित फर्जी और नियमों के विरुद्ध आवंटन की जांच कर रहा है। आरोप है कि इन भूखंडों का आवंटन कुछ अधिकारियों और उनसे जुड़े लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया था। पिछले वर्ष ईडी ने पंजाब के तत्कालीन प्रमुख सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और पीएसआईईसी के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर वर्ष 2012 के बाद आवंटित किए गए औद्योगिक भूखंडों का पूरा विवरण मांगा था। इसके साथ ही निगम या किसी अन्य जांच एजेंसी द्वारा की गई जांच, दर्ज प्राथमिकी और अन्य संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध कराने को कहा गया था। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने उस समय यह कहते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया था कि मामले की जांच पंजाब सतर्कता ब्यूरो द्वारा की जा रही है। मामले की संवेदनशीलता और ईडी के केंद्रीय जांच एजेंसी होने के कारण उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने अब यह मामला आवश्यक आदेशों के लिए मुख्य सचिव के पास भेज दिया है। ईडी की जांच पंजाब सतर्कता ब्यूरो की ओर से पीएसआईईसी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की जा रही है। जांच एजेंसियों को संदेह है कि औद्योगिक भूखंडों के आवंटन में नियमों की अनदेखी की गई और कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाया गया। सूत्रों के मुताबिक, ईडी की टीम अब भूखंड आवंटन से जुड़े दस्तावेजों, अधिकारियों की भूमिका, आवेदनों की प्रक्रिया और वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है। एजेंसी यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कथित अनियमितताओं से सरकारी खजाने को कितना नुकसान हुआ और इसमें किन अधिकारियों या निजी व्यक्तियों की भूमिका रही। छापेमारी के दौरान बरामद रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

संभल की तमन्ना मलिक को कांवड़ यात्रा पर प्रशासन की नोटिस

संभल (हिंस)। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के असमोली थाना क्षेत्र की तमन्ना मलिक की कांवड़ यात्रा पर प्रशासन की रोक लगा दी है। हरिद्वार से कांवड़ लाने की घोषणा करने वाली संभल की तमन्ना मलिक और उनके पति अमन त्यागी को स्थानीय प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। पुलिस ने दोनों की प्रस्तावित कांवड़ यात्रा को लेकर शांति भंग की आशंका जताई है। इसी आधार पर एसडीएम कोर्ट से नोटिस जारी किया गया है, जिसके तहत दोनों को जमानत कराकर मुचलका भरना होगा। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अमन त्यागी ने सवाल उठाते हुए कहा कि हरिद्वार जाकर कांवड़ लाने की घोषणा के कुछ समय बाद ही उन्हें नोटिस मिला। गौरतलब है कि पिछले वर्ष तमन्ना मलिक बुर्का पहनकर हरिद्वार से कांवड़ लेकर संभल पहुंची थीं। उस दौरान हिंदू समुदाय के कई लोगों ने उनका स्वागत किया था और उनकी कांवड़ यात्रा सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। कांवड़ का जल बालयोगी दीनानाथ द्वारा चढ़वाया गया था। इस विषय में एसडीएम संभल विकास चंद्र ने बताया कि थाना असमोली क्षेत्र से चालानी रिपोर्ट आई थी जिसके आधार पर तमन्ना मलिक और अमन त्यागी को 20-20 हजार रुपए के मुचलकों से पाबंद किया गया है।

राजस्थान में 2 करोड़ 55 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 2 लाख 18 हजार करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण स्वीकृत

जयपुर (हिंस)। राजस्थान में छोटी विनिर्माण इकाइयों-लघु उद्योगों से लेकर रेहड़ी-पटरी वालों के आर्थिक सशक्तीकरण के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में योजना के माध्यम से अब तक 2 करोड़ 55 लाख से अधिक लाभार्थियों को संस्थागत वित्त पोषण प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदेश में 2 करोड़ 55 लाख 91 हजार 381 लाभार्थियों को 2 लाख 18 हजार 423 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। इसमें 1 करोड़ 54 लाख 15 हजार से अधिक महिलाओं को 67 हजार 982 करोड़ रुपए से अधिक का मुद्रा ऋण भी शामिल है। इस प्रकार लगभग 60 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ महिलाओं ने योजना में बढ़-चढ़कर भाग लिया और ऋण प्राप्त किया। वहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही 23 लाख 74 से अधिक लाभार्थियों को 31 हजार 460 करोड़ रुपए का ऋण वितरित भी हो चुका है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में अतारांकित प्रश्न के जवाब में बताया कि देश के असंगठित क्षेत्र को बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध करवाने में मुद्रा योजना ने उल्लेखनीय कार्य किया है। जून 2026 तक योजना के अंतर्गत देशभर में 59 करोड़ 14 लाख से अधिक लोगों को 41 लाख 71 हजार करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है। उल्लेखनीय है कि गैर-कार्पोरेट, लघु उद्यमों को 20 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरूआत की गई थी। इस योजना में लाभार्थी वित्तपोषण की जरूरतों के अनुरूप शिशु, किशोर, तरुण और तरूण प्लस वर्गों के लिए ऋण आवेदन कर सकता है। करोड़ों लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराते हुए यह योजना विश्व के सबसे बड़े बिजनेस इको सिस्टम में से एक बन चुकी है। योजना से विनिर्माण इकाइयां, दुकानदार, फल-सब्जी विक्रेता, ट्रक-टैक्सी ऑपरेटर, खाद्य-सेवा इकाइयां, मशीन ऑपरेटर, छोटे उद्योग, कारीगर, खाद्य प्रसंस्करणकर्ता, रेहड़ी वालों को ऋण उपलब्ध करवाकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। ऋण लेने वालों में अधिकांश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो गैर-औपचारिक उधारदाताओं जैसे साहूकारों या दोस्तों और रिश्तेदारों से ऋण प्राप्त करते हैं। ऐसे में मुद्रा योजना संस्थागत वित्त की पहुंच सुनिश्चित करने उनकी आर्थिक उन्नति का जरिया बन रही है।

आईएसआई के दो आतंकी मॉड्यूल का खुलासा पंजाब में रेलवे ट्रैक धमाके की साजिश रचने वाले गिरफ्तार

चंडीगढ़ (हिंस)। पंजाब में अमृतसर पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के समर्थन से संचालित दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 4 नाबालिगों समेत कुल 9 आरोपियों को पकड़ा गया है। इनके कब्जे से 3 अवैध पिस्तौल, 9 जिंदा कारतूस और पेट्रोल से भरी 4 बोतलें बरामद की गई हैं। पंजाब पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने मंगलवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपी विदेश में बैठे आईएसआई हैंडलरों के संपर्क में थे और उनके निर्देश पर काम कर रहे थे। इन युवकों को आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्हें सुरक्षा प्रतिष्ठानों की रेकी करने, अवैध हथियार जुटाने और पंजाब में शांति एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित करने जैसे कार्य सौंपे गए थे। पुलिस को पता चला कि आरोपियों ने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। इन कैमरों से रिकॉर्ड की गई फुटेज कथित तौर पर विदेशी आईएसआई हैंडलरों को भेजी जा रही थी, ताकि संवेदनशील गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। करीब एक महीने पहले अमृतसर-दिल्ली रेलवे ट्रैक पर एक ओएचई (ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन) पोल पर सीसीटीवी कैमरा मिला था। कैमरे को बिजली आपूर्ति देने के लिए वहां सोलर पैनल भी लगाया गया था। जांच के दौरान पुलिस को कैमरे के सिम स्लॉट से एक सिम कार्ड मिला, जो गुरदेव के नाम पर पंजीकृत था। इसके आधार पर पुलिस ने गुरदेव को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों का कहना है कि अमृतसर के मोहकमपुरा, एयरपोर्ट और सी-डिवीजन थाना में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान की जा रही है। साथ ही इसके आगे और पीछे जुड़े संपर्कों, फंडिंग के स्रोत व विदेश से मिलने वाली आर्थिक मदद की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि क्या गिरफ्तार आरोपी किसी अन्य आतंकी साजिश या घटना में भी शामिल रहे हैं। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस का कहना है कि राज्य की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी तत्व को बख्शा नहीं जाएगा।

हिस्ट्रीशीटर हाजी अलीम के अवैध कब्जे पर बुलडोजर पांच करोड़ की सरकारी जमीन कराई कब्जामुक्त

अजमेर (हिंस)। अजमेर विकास प्राधिकरण (एडीए) और पुलिस ने मंगलवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए हिस्ट्रीशीटर एवं पूर्व पार्षद हाजी अलीम के कथित अवैध कब्जे से करीब डेढ़ बीघा सरकारी भूमि को मुक्त कराया। अधिकारियों के अनुसार कब्जामुक्त कराई गई भूमि की अनुमानित कीमत लगभग पांच करोड़ रुपए है। पुलिस के अनुसार सरकारी भूमि पर मैरिज गार्डन, चारदीवारी तथा अन्य व्यावसायिक निर्माण कर अवैध कब्जा किया गया था। पुलिस की रिपोर्ट और एडीए की जांच के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर बुलडोजर की सहायता से अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) हिमांशु जांगिड़ ने बताया कि अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क और अवैध संपत्तियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस जांच में कृष्णगंज थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर हाजी अलीम द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध व्यावसायिक निर्माण किए जाने की जानकारी मिलने पर एडीए को कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी गई थी। उन्होंने बताया कि हाजी अलीम वर्तमान में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में न्यायिक अभिरक्षा में है। एडीए के उप आयुक्त जयपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि पुलिस से प्राप्त शिकायत के बाद मामले की जांच कराई गई।

यूजीसी नियमों के विरोध पर करणी सेना का सरकार को सात दिन का अल्टीमेटम

जयपुर (हिंस)। यूजीसी के प्रस्तावित नियमों को वापस लेने की मांग को लेकर निकाली गई *सवर्ण न्याय यात्रा* के दौरान जयपुर में हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर श्री राजपूत करणी सेना ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने मंगलवार को सरकार को सात दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान बंद का आह्वान होगा और आगामी निकाय व पंचायत चुनावों में भाजपा के खिलाफ घर-घर जाकर प्रचार किया जाएगा। मकराना ने आरोप लगाया कि करणी सेना ने यूजीसी नियमों के विरोध में 24 दिनों तक करीब 800 किलोमीटर की पदयात्रा कर 50 से 60 कस्बों में लोगों को जागरूक किया। जयपुर पहुंचने से पहले कई दिनों तक प्रशासन से वार्ता चलती रही। प्रशासन शहर के बाहर ज्ञापन लेने पर अड़ा था, जबकि संगठन जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपना चाहता था। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने पानीपेच चौराहे तक जाने की अनुमति दी थी। लेकिन कालवाड़ पुलिया के नीचे पहुंचते ही बिना किसी चेतावनी के प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन चला दिया गया और लाठीचार्ज किया गया। मकराना का आरोप है कि महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों पर भी बल प्रयोग किया गया, जबकि आंदोलन पूरी तरह गांधीवादी तरीके से हो रहा था और प्रदर्शनकारी हाथों में गीता और संविधान लेकर चल रहे थे। मकराना ने दावा किया कि वाटर कैनन की चपेट में आने से देवराज सिंह पलाड़ा घायल हुए। घर पहुंचने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और सीने में दर्द की शिकायत पर पहले उन्हें निजी अस्पताल और बाद में एसएमएस अस्पताल ले जाया गया। जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि देवराज सिंह रावणा राजपूत समाज से थे और ओबीसी वर्ग से आते थे। करणी सेना ने इस मामले में एडिशनल एसपी बजरंग सिंह, डीवाईएसपी बीएल मीणा तथा एसएचओ गुरु भूपेंद्र को निलंबित करने की मांग की है। साथ ही मृतक के परिजनों को एक करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने की मांग भी रखी है। मकराना ने कहा कि यदि सात दिन में सरकार वार्ता नहीं करती और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो करणी सेना मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी।

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा

जोधपुर (हिंस)। अपने गृह नगर जोधपुर प्रवास के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने सरकार के मंत्रियों और विधायकों पर कटाक्ष किया। गहलोत ने कहा कि खींवसर विधायक रेवतराम डांगा पहले स्टिंग में पकड़े गए थे लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब डांगा ने 205 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया। वहीं केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने सब्सिड़ी के 90 लाख रुपए उठा लिए। संसद में मुद्दा बनने पर वापस जमा करवाया। हालांकि जमा कराने से क्राइम खत्म नहीं होता। उदयपुर के विधायकों पर भी आरोप है कि वे आदिवासी परिवारों को बंधक बनाकर जमीन कब्जा रहे हैं। गहलोत ने आज सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यशैली, आदिवासी क्षेत्रों की स्थिति, अरावली संरक्षण, मानगढ़ धाम सहित कई विषयों पर अपनी बात रखी। गहलोत ने आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुट है और चुनाव में भारी बहुमत से जीतेगी। छोटे-मोटे मतभेद हर दल में होते हैं, लेकिन कांग्रेस में कोई बड़ा मतभेद नहीं है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी मध्यप्रदेश और बिहार में हुए उपचुनाव में हारी है। राजस्थान में जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि चुनाव कब आए। गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है। करप्शन हो रहा है। मंत्री लोग जयपुर में मिलते नहीं हैं। सबके दरवाजे बंद हैं, लोग जाए कहां, कहीं जनसुनवाई नहीं हो रही। गहलोत ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद गंभीर दौर से गुजर रही है। हॉस्पिटलों में मरीजों को समय पर ऑक्सीजन, एक्स-रे और अन्य आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। कई मरीज इलाज के इंतजार में परेशान हैं, जबकि पेंशन और मृतकों के परिजनों को मिलने वाली आर्थिक सहायता भी समय पर नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि सरकार को हॉस्पिटलों में विशेष निगरानी दल बनाकर व्यवस्थाओं में सुधार करना चाहिए और यदि कहीं भ्रष्टाचार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन इसका खामियाजा आम मरीजों को नहीं भुगतना चाहिए। सरकार इस ओर पूरी तरह उदासीन बनी हुई है। कानून-व्यवस्था पर गहलोत ने कहा कि राजस्थान में हत्या, लूट, डकैती और ब्लाइंड मर्डर जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने लोहावट की हालिया घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि एक परिवार पर हमला हुआ, जिसमें दो बच्चे घायल हो गए और आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं बताती हैं कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और सरकार अपराध रोकने में विफल रही है। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग दोहराते हुए गहलोत ने कहा कि मानगढ़ के शहीदों ने देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था और उनके सम्मान में राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मानगढ़ आए थे और उस समय इस दिशा में उम्मीद जगी थी, लेकिन आज तक निर्णय नहीं हुआ। उन्होंने केंद्र सरकार से इस विषय पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की। वहीं उन्होंने अरावली को लेकर सरकार के गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया। उन्होंने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यदि अरावली नष्ट हुई तो सबसे अधिक नुकसान राजस्थान को होगा, लेकिन राज्य सरकार इस विषय पर गंभीर नजर नहीं आती। राम मंदिर चंदा मामले पर पूछे गए सवाल के जवाब में गहलोत ने कहा कि लोगों ने श्रद्धा से चंदा देकर जमीन खरीदी, निर्माण कराया और सहयोग किया। उन्होंने कहा कि यदि कहीं वित्तीय अनियमितताओं या घोटालों के आरोप सामने आते हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए।

उप्र मानसून सत्र : प्रदेश सरकार ने पेश किया 59 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट, केंद्र से मिलेगी 11 हजार करोड़ की सहायता

लखनऊ (हिंस)। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शून्यकाल में विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे बीच वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए अनुपूरक बजट में पेश किया। उन्होंने कुल 59,019.54 करोड़ रुपए की अनुपूरक बजट मांग (अतिरिक्त बजट) पेश किया। इस बजट में केंद्र सरकार से 11,240.97 करोड़ की मदद अंशदान (हिस्सेदारी) के रूप में मिलेगी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना बार -बार विपक्षी सदस्यों को अपनी सीट पर बैठने और चर्चा में भाग लेने का आग्रह करते रहे, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी जारी रखी। इस बीच जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा और तेज कर दिया। विपक्षी सदस्य नारे लगा रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि विपक्ष न तो सदन की मर्यादा का ख्याल रखता है और संवैधानिक मूल्यों का ही पालन कर रहा है। आज सदन में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए राज्य सरकार ने कुल 59,019.54 करोड़ रुपए की अनुपूरक बजट मांग (अतिरिक्त बजट) पेश किया। इस बजट में केंद्र सरकार से 11,240.97 करोड़ की मदद अंशदान (हिस्सेदारी) के रूप में मिलेगी। केंद्र से मिलने वाली राशि को घटाने के बाद राज्य सरकार के खजाने (समेकित निधि) पर 47,778.57 करोड़ रुपए का शुद्ध वित्तीय बोझ पड़ेगा। इस खर्च का इंतजाम सरकार टैक्स (कर) और गैर-टैक्स (करेतर) से होने वाली अपनी राजस्व आय के तय लक्ष्यों को पूरा करके तथा फालतू (अनुत्पादक) खर्चों में कटौती करके करेगी। वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए पेश किए गए अनुपूरक बजट में राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। औद्योगिक विकास एवं भारी उद्योगों को सबसे बड़ा हिस्सा दिया गया है, जिसके तहत भारी एवं मध्यम उद्योग विभाग के लिए 1,30,301.92 लाख रुपए का राजस्व खर्च और 20,905.88 करोड़ रुपए का भारी-भरकम पूंजीगत बजट मंजूर किया गया है। इसके अलावा हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग को 1,502.79 लाख रुपए राजस्व और 12,500.00 लाख रुपए पूंजीगत मद में दिए गए हैं, जबकि मुद्रण तथा लेखन सामग्री के पूंजीगत कार्यों हेतु 2,350.00 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए ग्राम्य विकास विभाग को 8,103.51 लाख रुपए राजस्व तथा 14,18,471.95 लाख रुपए का पूंजीगत आवंटन प्राप्त हुआ है। ऊर्जा क्षेत्र (बिजली व्यवस्था) के लिए कुल मिलाकर 7,02,227.00 लाख रुपए (भारित राशि सहित) राजस्व मद में और 40,000.00 लाख रुपए पूंजीगत मद में आवंटित किए गए हैं। वहीं स्थानीय निकायों और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज विभाग को 15,633.00 लाख रुपए का राजस्व तथा 13,998.00 लाख रुपए का पूंजीगत बजट प्रदान किया गया है। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिये जरूरी राशि का प्रबंध किया गया है। कृषि विभाग को 13,237.76 लाख रुपए राजस्व और 15,900.00 लाख रुपए पूंजीगत विकास के लिए दिए गए हैं। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के हिस्से में 24,480.37 लाख रुपए राजस्व और 1,005.02 लाख रुपए पूंजीगत आवंटन आया है। पशुपालन विभाग के लिए 2,497.84 लाख रुपए राजस्व व 4,486.66 लाख रुपए पूंजीगत, दुग्ध विकास विभाग के लिए 20,425.10 लाख रुपए राजस्व, मत्स्य विभाग के लिए 300.00 लाख रुपए राजस्व व 600.00 लाख रुपए पूंजीगत, तथा भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग को 200.00 लाख रुपए का राजस्व बजट मंजूर हुआ है। इस अनुपूरक बजट में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रभाग के लिए राजस्व मद में 10.00 लाख रुपए और पूंजीगत मद में 10.00 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। एलोपैथी चिकित्सा प्रभाग को सबसे बड़ा हिस्सा मिला है, जिसके अंतर्गत राजस्व मद में 1,10,000.00 लाख रुपए तथा पूंजीगत मद में 9,600.00 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा प्रभाग के लिए राजस्व मद में 25.00 लाख रुपए और पूंजीगत मद में 2,300.00 लाख रुपए रखे गए हैं।

नेपाल में तनाव के मद्देनजर बिहार सीमा के भीमनगर में बायोमैट्रिक जांच हुआ अनिवार्य

सुपौल (हिंस)। नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में हाल के दिनों में हुई हिंसक झड़पों के बाद भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं। नेपाल में हुई हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं। हालात को नियंत्रित करने के लिए नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल और सेना को कई जिलों में तैनात करना पड़ा। स्थिति सामान्य बनाने के लिए नेपाल सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर निगरानी की। नेपाल की इन घटनाओं के मद्देनजर सीमावर्ती भारतीय इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप से सीमा पर लगातार निगरानी रख रही हैं। अधिकारियों द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है, ताकि किसी भी संभावित चुनौती से समय रहते निपटा जा सके। बढ़ी हुई सुरक्षा के तहत अब नेपाल जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए बायोमैट्रिक स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी गई है। पहले कई यात्री मोबाइल में मौजूद आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र दिखाकर सीमा पार कर लेते थे, लेकिन अब सभी यात्रियों को वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने के साथ बायोमैट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह व्यवस्था महिलाओं, पुरुषों और बच्चों सहित सभी यात्रियों पर समान रूप से लागू की गई है। सोमवार शाम भीमनगर स्थित एसएसबी चेक पोस्ट पर नेपाल आने-जाने वाले लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलीं। यात्रियों का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति की अलग-अलग जांच होने से सीमा पार करने में पहले की अपेक्षा अधिक समय लग रहा है। स्थानीय लोगों ने जांच प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए भीमनगर बॉर्डर पर अतिरिक्त कर्मियों और संसाधनों की तैनाती की मांग की है। एसएसबी अधिकारियों के अनुसार मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह एहतियात के तौर पर लागू की गई है। उनका कहना है कि सीमा की सुरक्षा को मजबूत करने और दोनों देशों के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहचान सत्यापन और बायोमैट्रिक जांच आवश्यक है। अधिकारियों ने संकेत दिया कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह कड़ी जांच व्यवस्था फिलहाल आगे भी जारी रह सकती है।

भारत के निजी विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि जुलाई में 5 साल के निचले स्तर पर

नई दिल्ली

भारत के निजी क्षेत्र में विनिर्माण गतिविधियों की वृद्धि जुलाई माह में पांच वर्षों में सबसे सुस्त गति से हुई है। एक निजी सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई है। एचएसबीसी का भारत का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई), जो विनिर्माण गतिविधियों में बदलाव पर नजर रखता है, जून के 54.2 से गिरकर जुलाई में 53.5 पर पहुंच गया।

एचएसबीसी पीएमआई जून के 54.2 से गिरकर 53.5 हुआ

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, कुल बिक्री में गिरावट और नए ऑर्डर व नौकरी सृजन में कमी को इस सुस्ती का मुख्य कारण बताया गया है। जुलाई का 53.5 का आंकड़ा अगस्त 2021 के बाद सबसे कम है, जब यह 52.3 था। हालांकि, यह सूचकांक 50 के स्तर से ऊपर बना हुआ है, जो गतिविधियों में विस्तार का संकेत देता है। यह लगातार 57वां महीना है जब विनिर्माण गतिविधियों में विस्तार देखा गया है। एचएसबीसी की एक चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट ने बताया कि जुलाई में आपूर्तिकर्ता की आपूर्ति के समय का सूचकांक बढ़ा है, जो आपूर्ति श्रृंखला में सुधार का संकेत है। हालांकि, मध्य पूर्व में फिर से बढ़े तनाव ने इन सुधारों के स्थायित्व पर नए संदेह पैदा कर दिए हैं। इसके चलते विनिर्माता बफर बना रहे हैं, जिससे इनपुट और तैयार माल दोनों की इन्वेंट्री में बढ़ोतरी हुई है।

सर्वेक्षण के अनुसार नए ऑर्डर में वृद्धि चार साल से अधिक समय में दूसरी सबसे कमजोर रही, जिसका मुख्य कारण बाजार की मुश्किल होती स्थितियां और ग्राहकों की कम दिलचस्पी बताई गई है। बिक्री के मामले में भी वृद्धि की गति 2022 के मध्य के बाद से सबसे धीमी थी। जुलाई में उपभोक्ता सामान क्षेत्र सबसे कमजोर रहा, जिसमें नए ऑर्डर और आउटपुट में काफी कम वृद्धि देखी गई, जबकि इंटरमीडिएट और कैपिटल गुड्स बनाने वाली कंपनियों ने दोनों पैमानों पर मजबूत विस्तार दर्ज किया। इसके अतिरिक्त अतिरिक्त इनपुट की खरीद 31 महीने के निचले स्तर पर आ गई। भारत के विनिर्माण क्षेत्र में नौकरी के अवसर बढ़ने की रफ्तार लगातार तीसरे महीने धीमी रही और यह लगातार 29 महीनों की वृद्धि में सबसे धीमी दर थी। हालांकि, लागत का दबाव पांच महीनों में सबसे कम स्तर पर आ गया, लेकिन कंपनियों ने विशेषकर सामान की आवाजाही के लिए ज्यादा कीमतें बताईं। इस दौरान बिक्री की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी हुई, जो मोटे तौर पर जून जैसी ही थी।

न्यूज ब्रीफ

अब 25,000 तक बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी भी पीएफ के दायरे में, पीएफ की वेज सीलिंग लिमिट 15,000 से बढ़कर 25,000 रुपए हुई

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्रोविडेंड फंड (पीएफ) से जुड़े नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। पीएफ की वेज सीलिंग लिमिट को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है, जिसका सीधा असर लाखों नौकरीपेशा लोगों की मासिक सैलरी और रिटायरमेंट फंड पर पड़ेगा। इस बदलाव से अब ज्यादा कर्मचारी पीएफ और पेंशन योजना (ईपीएस) के दायरे में आ सकेंगे, हालांकि शुरुआत में हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि में रिटायरमेंट सुरक्षा मजबूत होगी। पहले नियम के अनुसार, जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता मिलाकर 15,000 रुपये तक होता था, उनके लिए पीएफ कटवाना अनिवार्य था। 15,000 रुपये से अधिक आय वाले कर्मचारी इससे बाहर रह सकते थे। नई लिमिट 25,000 रुपये होने के बाद अब 15,001 रुपये से 25,000 रुपये तक बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी भी पीएफ के दायरे में आ जाएंगे, जिससे उन्हें बचत के साथ-साथ पेंशन का लाभ भी मिलेगा। इस बदलाव से पीएफ में ज्यादा योगदान जाने के कारण हर महीने हाथ में आने वाली सैलरी में कुछ कमी देखी जा सकती है। दरअसल, कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा पीएफ खाते में जमा होता है और कंपनी भी अपनी ओर से इतना ही योगदान देती है। उदाहरण के लिए, 22,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को अब 2,640 रुपये पीएफ के रूप में कटवाने होंगे, जबकि पहले वह दायरे में नहीं था। इसी तरह, 25,000 रुपये बेसिक सैलरी पर पीएफ योगदान 1,800 रुपये (15,000 पर) से बढ़कर 3,000 रुपये (25,000 पर) हो जाएगा। यह बदलाव कई कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट सुरक्षा को बढ़ाने वाला साबित होगा, खासकर उनके लिए जो पहले इस सीमा के कारण पीएफ और पेंशन योजना से नहीं जुड़ पा रहे थे। हालांकि, कंपनियों और सरकार पर भी इससे अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा, लेकिन यह कदम कर्मचारियों की लंबी अवधि की आर्थिक सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेगा।

संजय मल्होत्रा बुधवार सुबह 10 बजे करेंगे एमपीसी के निर्णयों का ऐलान

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय समीक्षा बैठक दूसरे दिन मंगलवार को भी चल रही है। सोमवार से चल रही द्विमासिक एमपीसी समीक्षा बैठक के फैसलों के 'निर्णय' का ऐलान 5 अगस्त को आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा सुबह 10 बजे करेंगे। आरबीआई के मुताबिक रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा का मौद्रिक नीति वक्तव्य 5 अगस्त को सुबह 10 बजे भारत मानक समय (आईएसटी) निर्धारित है। इसके बाद दोपहर 12 बजे मॉनेटरी पॉलिसी के बाद की प्रेस कांफ्रेंस होगी। आर्थिक मामलों के जानकारों का मानना है कि 6 सदस्यों वाली मौद्रिक नीति समिति जून की बैठक की तरह ही इस बार भी नीतिगत ब्याज दर रेपो रेट को 5.25 फीसदी पर बरकरार रखेगी। एसबीआई रिसर्च के अनुसार आरबीआई के नीतिगत दरों को जस का तस रखने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि अगले दो तिमाहियों में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (महंगाई) के 5 फीसदी से ऊपर रहने का अनुमान है।

टारगेट की एआई उड़ान, खुदरा कारोबार में तकनीक का नया अध्याय, डिजाइन से डिजिटल अनुभव तक, हर जगह एआई का कमाल

बेंगलुरु। अमेरिकी खुदरा दिग्गज टारगेट ग्राहकों की बदलती जरूरतों के अनुरूप ढलने और अपने परिचालन को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग कर रहा है। कंपनी की उद्यम रणनीति को नए सिरे से परिभाषित करने और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने में भारत के बेंगलुरु स्थित नवाचार केंद्र की भूमिका केंद्रीय है। टारगेट के मुख्य सूचना अधिकारी प्रैट वेमाना के अनुसार, कंपनी एआई का उपयोग कर अपनी रणनीति को नए सिरे से गढ़ रही है और एआई की दुनिया में तेजी से हो रहे बदलावों के अनुसार अपने परिचालन में तकनीक को अधिक शामिल कर रही है। टारगेट इंडिया के एक कार्यकारी अ?धिकारी ने बताया कि उनकी तीन मुख्य प्राथमिकताएं हैं: पहला एआई के साथ उद्यम रणनीति को मजबूत करना; दूसरा, एआई ढांचे में बदलाव को आधार देने के लिए तकनीक और आर्किटेक्चर में परिवर्तन लाना और तीसरा, काम करने के तरीके को बेहतर बनाना। उन्होंने जोर दिया कि कंपनी यह समझ रही है कि एआई कैसे शैली, डिजाइन और अतिथि अनुभव को उन्नत कर रहा है।

सब्सक्रिप्शन के लिए एजियस टेक्नोलॉजीज का आईपीओ लॉन्च, 11 अगस्त को हो सकती है लिस्टिंग

नई दिल्ली

रोबोटिक्स और इंटेलिजेंट ऑटोमेशन सेक्टर के लिए काम करने वाली कंपनी एजियस टेक्नोलॉजीज का 23.71 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च कर दिया गया। इस आईपीओ में छह अगस्त तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद सात अगस्त को शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा, जबकि 10 अगस्त को अलॉटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर 11 अगस्त को बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं। लॉन्चिंग के बाद दोपहर 1:30 बजे तक इस आईपीओ को 20 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिल चुका था।

इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 100 रुपये से लेकर 105 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 1,200 शेयर का है। इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स को दो लॉट यानी 2,400 शेयरों के लिए बोली लगाना होगा, जिसके लिए उन्हें 2,52,000 रुपये का निवेश करना होगा। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 22,58,400 शेयर जारी किए जा रहे हैं।

इस आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए 42.72 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इसके अलावा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए 29.97 प्रतिशत हिस्सा और नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (एनआईआई) के लिए 12.91 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है। इसके अलावा मार्केट मेकर के लिए 14.40 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इस इश्यू के लिए टर्नअराउंड कॉरपोरेटर एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है, जबकि स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है। प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी का मार्केट मेकर है।

एजियस टेक्नोलॉजीज की वित्तीय स्थिति की बात करें, तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत मजबूत बनी रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी को 93 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 1.39 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। वहीं पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का शुद्ध लाभ उछल कर 4.02 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया।

इस दौरान कंपनी की राजस्व प्राप्ति में लगातार बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में इसे 15.28 करोड़ रुपये का कुल राजस्व प्राप्त हुआ, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 21.90 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी को 41.22 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस अवधि में कंपनी पर लदा कर्ज का बोझ मामूली उतार-चढ़ाव के बावजूद बढ़ता गया। वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में कंपनी पर 4.16 करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में थोड़ा कम होकर 4.10 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें, तो इस वित्त वर्ष के दौरान कंपनी पर लदे कर्ज का बोझ उछल कर 11.93 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया।

कंपनी का रिजर्व और सरप्लस भी इस अवधि में उतार-चढ़ाव होता रहा। वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में कंपनी का रिजर्व और सरप्लस 5.82 करोड़ रुपये के स्तर पर था, जो वित्त वर्ष वित्त वर्ष 2024-25 में कम होकर 5.30 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें, तो इस दौरान कंपनी का रिजर्व और सरप्लस बढ़ कर 9.28 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया था। इस अवधि में कंपनी के नेटवर्थ में भी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में ये 5.83 करोड़ रुपये के स्तर पर था, जो 2024-25 में बढ़ कर 11.42 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। वहीं पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का नेटवर्थ 15.40 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

इसी तरह ईबीआईटीडीए (अर्निंग बिफोर इंट्रेस्ट, टैक्सेज, डिप्रेशिएशंस एंड एमॉर्टाइजेशन) 2023-24 में 1.66 करोड़ रुपये के स्तर पर था, जो 2024-25 में बढ़ कर 3.13 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का ईबीआईटीडीए 6.48 करोड़ रुपये के स्तर पर था।

एलआईसी में सरकार बेचेगी 6.5 फीसदी हिस्सेदारी

मुंबई

शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में अपनी हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के जरिए बेचने का फैसला किया है। पहले चरण में 2.5 फीसदी हिस्सेदारी बेची जाएगी, जिसे ग्रीन शू ऑप्शन के तहत कुल 6.5 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है।

आम निवेशकों को मिलेगा शेयर खरीदने का मौका

सरकार का यह कदम सेबी के न्यूनतम सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग नियमों के अनुपालन हेतु उठाया जा रहा है। सरकार ने इस ऑफर फॉर सेल के लिए 382 रुपए प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस निर्धारित किया है, जिसका अर्थ है कि इससे कम कीमत पर शेयर नहीं खरीदे जा सकेंगे। वर्तमान में, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में सरकार की करीब 96.5 फीसदी हिस्सेदारी है। इस पेशकश में पहले गैर-खुदरा निवेशकों (संस्थागत निवेशक) को हिस्सा खरीदने का मौका मिलेगा, जिसके बाद खुदरा निवेशक भी अगले दिन अपनी बोली लगा सकेंगे। पहले चरण में 2.5 फीसदी हिस्सेदारी बेची जाएगी, लेकिन निवेशकों की अच्छी मांग पर ग्रीन शू ऑप्शन के तहत 4 फीसदी अतिरिक्त हिस्सेदारी भी बेची जा सकती है, यानी कुल 6.5 फीसदी तक शेयर बाजार में आ सकते हैं। सरकार का यह निर्णय केवल पूंजी जुटाने के लिए ही नहीं, बल्कि एक नियामक उद्देश्य के लिए भी है। सेबी के नियमों के अनुसार शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में कम से कम 25 फीसदी हिस्सेदारी आम निवेशकों (पब्लिक) के पास होनी चाहिए।

एलआईसी जिसकी लिस्टिंग साल 2022 में हुई थी और जो देश का सबसे बड़ा आईपीओ था, अब इस ओएफएस के माध्यम से अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता को बढ़ाएगी। इस कदम से कंपनी में शेयरों की तरलता (लिक्विडिटी) बढ़ेगी और वह नियामक मानकों के अधिक करीब पहुंचेगी। विश्लेषकों का मानना है कि एलआईसी जैसी देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी में इस तरह की हिस्सेदारी बिक्री से निवेशकों को एक निर्धारित मूल्य पर निवेश का अवसर मिलता है, और सरकार को भी पूंजी जुटाने में मदद मिलती है।

यूपीआई नियमों में होगा बदलाव, भविष्य में लग सकता है एमडीआर

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड पर जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) की व्यवस्था खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिससे भविष्य में यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लगाने का अधिकार मिल सकेगा। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ग्राहकों के लिए कोई नया शुल्क लागू नहीं किया गया है और इसका उद्देश्य यूपीआई यूजर्स से अतिरिक्त चार्ज वसूलना नहीं है। यदि भविष्य में एमडीआर लागू भी होता है, तो इसका असर मुख्य रूप से कारोबारियों (मर्चेंट्स) पर पड़ सकता है। यह प्रस्ताव पेमेंट एक्ट की धारा 10ए को हटाने के लिए है, जो वर्तमान में डिजिटल भुगतान पर एमडीआर लगाने से रोकती है। संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति के अनुसार, देश के 88 फीसदी डिजिटल भुगतान यूपीआई से होते हैं और अरबों ट्रांजैक्शन की बढ़ती लागत ने बैंकों व पेमेंट कंपनियों पर दबाव बढ़ाया है। डिजिटल पेमेंट उद्योग लंबे समय से जीरो एमडीआर नीति की समीक्षा की मांग कर रहा है, क्योंकि प्रोत्साहन राशि वास्तविक लागत से कम है। कुछ संगठनों ने बड़े कारोबारियों पर सीमित एमडीआर और छोटे को छूट देने का सुझाव दिया है।

ईरान वार्ता और हॉर्मुज स्ट्रेट की अटकलों से सोना-चांदी चमके

सोने के भाव 644 तेज होकर 1,43,600 रुपए, चांदी 1,397 चढ़कर 2,19,150 रुपए

नई दिल्ली

वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच मंगलवार को सोना और चांदी के वायदा भाव में जोरदार तेजी दर्ज की गई। अमेरिका-ईरान वार्ता और हॉर्मुज स्ट्रेट के दोबारा खुलने की संभावनाओं पर निवेशकों की पैनी नजर बनी हुई है, जिसने इन कीमती धातुओं को मजबूत सहारा दिया। खबर लिखे जाने तक ग्लोबल कॉमेक्स पर सोना 4,115 डॉलर और चांदी 58.90 डॉलर प्रति औंस के करीब कारोबार कर रही थी, जबकि घरेलू एमसीएक्स पर सोना 1,43,600 रुपये और चांदी 2,19,150 रुपये के करीब पहुंच गई।

घरेलू वायदा बाजार एमसीएक्स पर सोने के बेंचमार्क अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत 644 रुपये की मजबूत तेजी के साथ 1,43,559 रुपये पर हुई, जबकि पिछला बंद भाव 1,42,915 रुपये था। खबर लिखे जाने के समय यह कॉन्ट्रैक्ट 692 रुपये की तेजी के साथ 1,43,607 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

इस साल सोने ने 1,80,779 रुपये का सर्वोच्च स्तर छुआ था। वहीं चांदी के सितंबर कॉन्ट्रैक्ट ने भी रफ्तार पकड़ी। यह 1,397 रुपये की तेजी के साथ 2,18,143 रुपये पर खुला, जो पिछले बंद भाव 2,16,746 रुपये से काफी ऊपर था। वर्तमान में यह 2,404 रुपये की छलांग के साथ 2,19,150 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहा था।

चांदी ने इस साल 4,20,048 रुपये प्रति किलो का उच्चतम स्तर बनाया था। अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स पर भी सोने और चांदी के वायदा भाव में तेज उछाल देखा गया। सोना 4,109.60 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला, जो पिछले क्लोजिंग प्राइस 4,090.50 डॉलर प्रति औंस से अधिक था। खबर लिखे जाने तक यह 23.30 डॉलर की तेजी के साथ 4,113.80 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। इस साल सोने ने 5,586.20 डॉलर का सर्वोच्च स्तर छुआ था। चांदी का वायदा भाव 58.38 डॉलर प्रति औंस पर खुला, जबकि पिछला क्लोजिंग प्राइस 57.85 डॉलर था। यह भी तेजी बरकरार रखते हुए 1.03 डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 58.88 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया था। चांदी के भाव ने इस साल 121.79 डॉलर का उच्चतम स्तर छू लिया था।

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत, एशिया में भी मिला-जुला कारोबार

नई दिल्ली

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान मजबूती के साथ बंद हुए थे। डाउ जॉन्स फ्यूचर्स भी फिलहाल बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार भी पिछले सत्र के दौरान हरे निशान में बंद होने में सफल रहे। वहीं एशियाई बाजार में मिला-जुला कारोबार हो रहा है।

पश्चिम एशिया में ईरान के साथ समझौता हो जाने की उम्मीद की वजह से अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान लगातार तेजी का रुख बना रहा। एस एंड पी 500 इंडेक्स 110.78 अंक यानी 1.48 प्रतिशत उछल कर 7,600.50 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह नैस्डेक ने 540.04 अंक यानी 2.13 प्रतिशत की जबरदस्त छलांग लगा कर 25,913.90 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। वहीं डाउ जॉन्स फ्यूचर्स फिलहाल 151.99 अंक यानी 2.13 प्रतिशत की बढ़त के साथ 53,330.40 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

यूरोपीय बाजार मे भी पिछले सत्र के दौरान तेजी का रुख बना रहा। सीएसी इंडेक्स 104.18 अंक यानी 1.21 प्रतिशत की मजबूती के साथ 8,613.82 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह डीएएक्स इंडेक्स ने 372.07 अंक यानी 1.43 प्रतिशत की छलांग लगा कर 26,001.31 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। वहीं ब्रिटेन के फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज में छुट्टी होने की वजह से एफटीएसई इंडेक्स में पिछले सत्र के दौरान कोई हलचल नहीं रही।

एशियाई बाजार में मिला-जुला कारोबार हो रहा है। एशिया के नौ बाजार में से पांच के सूचकांक कमजोरी के साथ लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि चार सूचकांक मजबूती के साथ हरे निशान में बने हुए हैं। जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स 0.58 प्रतिशत की मजबूती के साथ 6,270.48 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.30 प्रतिशत की तेजी के साथ 5,629.18 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसके अलावा शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.16 प्रतिशत उछल कर 3,815.59 अंक के स्तर पर और सेट कंपोजिट इंडेक्स 0.09 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,623.36 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। दूसरी ओर, गिफ्ट निफ्टी 0.04 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 24,656 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह ताइवान वेटेड इंडेक्स 0.12 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 43,335.92 अंक के स्तर पर आ गया है। कोस्पी इंडेक्स में बड़ी गिरावट नजर आ रही है। फिलहाल यह सूचकांक 1.08 प्रतिशत फिसल कर 6,190.06 अंक के स्तर तक पहुंच गया है। इसके अलावा हैंग सेंग इंडेक्स 98.40 अंक यानी 0.38 प्रतिशत टूट कर 25,911 अंक के स्तर पर और निक्केई इंडेक्स 202.90 अंक यानी 0.32 प्रतिशत लुढ़क कर 63,552 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया-ए महिला टीम घोषित टायला व्लेमिंक और डार्सी ब्राउन की वापसी

नई दिल्ली

अगले महीने भारत दौरे पर आने वाली ऑस्ट्रेलिया-ए महिला क्रिकेट टीम की मंगलवार को 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है। अनुभवी तेज गेंदबाज टायला व्लेमिंक और डार्सी ब्राउन टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई करेंगी। यह दौरा तीन सप्ताह तक चलेगा, जिसमें दोनों टीमें तीन टी20, तीन एकदिवसीय और एक चार दिवसीय मुकाबला खेलेंगी।

भारत दौरे के दौरान तीनों टी20 मुकाबले न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसके बाद तीन एकदिवसीय मैच मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में होंगे, जबकि चार दिवसीय मुकाबला धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

इस दौरे के साथ 27 वर्षीय तेज गेंदबाज टायला व्लेमिंक लंबे समय बाद प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वापसी करेंगी। चोटों से लगातार जूझने के कारण उनका करियर काफी प्रभावित रहा है। उन्होंने अप्रैल में ग्रीन बनाम गोल्ड अभ्यास मैच के जरिए वापसी की थी, जो 2024 टी20 विश्व कप में कंधे की गंभीर चोट के बाद उनका पहला मुकाबला था। इस वर्ष अप्रैल में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने लगातार चोटों के चलते उनका केंद्रीय अनुबंध भी समाप्त कर दिया था।

वहीं, डार्सी ब्राउन को टी20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में जगह नहीं मिली थी। उनकी अनुपस्थिति में बाएं हाथ की तेज गेंदबाज लूसी हैमिल्टन ने टीम में अपनी जगह मजबूत कर ली थी। अब ब्राउन को ऑस्ट्रेलिया-ए टीम के जरिए फिर से खुद को साबित करने का मौका मिलेगा। राष्ट्रीय चयनकर्ता शॉन फ्लेगलर ने कहा, 'टायला को फिर से हरे और सुनहरे रंग की जर्सी में देखना और डार्सी की वापसी हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। दोनों के पास अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव है और युवा खिलाड़ियों को उनसे सीखने का शानदार अवसर मिलेगा। उन्होंने आगे कहा, 'यह दौरा खिलाड़ियों के लिए उपमहाद्वीपीय परिस्थितियों में खेलने और मजबूत अंतरराष्ट्रीय प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ खुद को परखने का बेहतरीन अवसर है। करियर के शुरुआती दौर में भारतीय परिस्थितियों का अनुभव भविष्य में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होता है। एकदिवसीय श्रृंखला में ताहलिया विल्सन टीम की कप्तानी करेंगी, जबकि निकोल फाल्टम टी20 टीम और रेचल ट्रेनामैन चार दिवसीय मैच में ऑस्ट्रेलिया-ए की कप्तान होंगी। टीम के आधे से अधिक खिलाड़ी 25 वर्ष या उससे कम उम्र के हैं, जिनमें 21 वर्षीय ऑलराउंडर फ्रैंकी निकलिन और सियाना जिंजर भी शामिल हैं।

न्यूज ब्रीफ

डीपीएल 2026: ट्रॉफी जीतने के लिए हर खिलाड़ी का योगदान जरूरी : यश धुल

नई दिल्ली। दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) 2026 में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के खिलाफ 210 रन का विशाल लक्ष्य हासिल करने के बाद सेंट्रल दिल्ली किंग्स के कप्तान यश धुल ने टीम के सामूहिक प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि किसी भी टीम को चैंपियन बनने के लिए अलग-अलग मुकाबलों में अलग-अलग खिलाड़ियों का योगदान जरूरी होता है। यश धुल ने कहा, 'हमारे लिए सबसे सकारात्मक बात यह है कि हर मैच में कोई न कोई नया खिलाड़ी आगे आकर जिम्मेदारी निभा रहा है। पिछले मैच में वंश बेदी ने शानदार प्रदर्शन किया था, जबकि जोंटी सिद्धू और आदित्य भंडारी ने बेहतरीन पारियां खेलीं। इससे पूरी टीम का आत्मविश्वास बढ़ता है कि हम किसी भी लक्ष्य का पीछा कर सकते हैं। ट्रॉफी जीतने के लिए अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग खिलाड़ियों का योगदान जरूरी होता है। उन्होंने जोंटी सिद्धू और आदित्य भंडारी की मैच जिताऊ साझेदारी की भी जमकर तारीफ की। धुल ने कहा, 'जोंटी और आदित्य के बीच हुई साझेदारी बेहद अहम रही। हमने पिछले सीजन से ही जोंटी पर भरोसा जताया है और उन्होंने शानदार परिपक्वता दिखाई। शुरुआती विकेट गिरने के बाद उन्होंने पारी को बेहतरीन तरीके से संभाला। युवा खिलाड़ियों को उनकी बल्लेबाजी से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मैच के हीरो रहे जोंटी सिद्धू ने कहा कि बड़ी रन-चेज के दौरान शांत रहना उनकी सफलता की सबसे बड़ी वजह रही। उन्होंने कहा, मेरी योजना पूरे रन चेज के दौरान शांत रहने की थी। बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। मैं लगातार आदित्य भंडारी से कह रहा था कि हमें हर ओवर में सिर्फ एक-दो चौकों की जरूरत है। अगर हम धैर्य बनाए रखेंगे तो मैच हमारे पक्ष में आ जाएगा। खुशी है कि हमारी योजना सफल रही। जोंटी ने बताया कि टीम को पहले 200 से अधिक रन का सफल पीछा करने का अनुभव था, जिससे खिलाड़ियों का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ था। उन्होंने कहा, 'ड्रेसिंग रूम में ज्यादा चर्चा नहीं हुई क्योंकि हम इससे पहले भी 200 से अधिक रन का लक्ष्य हासिल कर चुके थे। हमें पूरा विश्वास था कि अगर हम अपनी प्रक्रिया पर कायम रहे तो दोबारा भी ऐसा कर सकते हैं।

पाकिस्तान ने बल्लेबाजी कोच बदला, दक्षिण अफ्रीका के माइक स्मिथ को सौंपी जिम्मेदारी

इस्लामाबाद। टेस्ट क्रिकेट में लगातार खराब बल्लेबाजी प्रदर्शन के बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर और अनुभवी कोच माइक स्मिथ को राष्ट्रीय टेस्ट टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त करने का फैसला किया है। वह असद शफीक की जगह यह जिम्मेदारी संभालेंगे। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पीसीबी इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट श्रृंखला से पहले इस नियुक्ति की औपचारिक घोषणा कर सकता है। बताया जा रहा है कि बोर्ड द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाने के बाद माइक स्मिथ का चयन किया गया और वह इंग्लैंड दौरे से टीम के साथ जुड़ेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, असद शफीक के बल्लेबाजी कोच के रूप में कामकाज को लेकर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि वह एक साथ पुरुष और महिला चयन समिति के सदस्य होने के अलावा कराची स्थित पीसीबी अकादमी के प्रमुख की जिम्मेदारी भी निभा रहे थे। ऐसे में बल्लेबाजी कोच की भूमिका पर पूरा ध्यान नहीं दे पाने की आलोचना हो रही थी। पिछले तीन वर्षों में पाकिस्तान ने बल्लेबाजी कोच के पद पर कई बदलाव किए हैं।

शफीक के शतक और बाबर के अर्धशतक से पाकिस्तान ने पहली पारी में बनाये 266/2

जमैका। अब्दुला शफीक की शतकीय पारी के साथ ही कप्तान बाबर आजम व युवा अजान औवैस के अर्धशतकों की सहायता से पाकिस्तान ने मेजबान वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में अच्छी वापसी की है। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पर पाक ने अपनी पहली पारी में दो विकेट पर 266 रन बना लिए। खेल समाप्त होने के समय शफीक 107 रन बनाकर खेल रहे थे जबकि बाबर आजम ने 86 रन बनाये थे। इस प्रकार पाक टीम अब वेस्टइंडीज के 344 रनों के स्कोर से केवल 78 रन ही पीछे है। अजान औवैस और इमाम उल हक ने पाक की दूसरी पारी की शुरुआत की। इमाम बड़ी पारी नहीं खेल पाये और केवल 14 रन ही बना पाये। इसके बाद युवा सलामी बल्लेबाज अजान औवैस ने 71 गेंदों में 55 रन बना दिये। अजान के आउट होने के बाद, अब्दुला शफीक और बाबर आजम ने तेजी से रन बनाये। दोनों ने मिलकर एक अच्छी साझेदारी बनाई, जिसने पाक को मैच में आगे बढ़ने का अवसर मिल गया।

जूनियर एशिया कप की तैयारियों के लिए भारत में आठ मैच खेलेगी मलेशियाई हॉकी टीम

बेंगलुरु

आगामी जूनियर एशिया कप 2026 की तैयारियों के लिए मलेशियाई अंडर-21 पुरुष हॉकी टीम भारत दौरे पर है। इस दौरे में मलेशियाई टीम भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम और साई टीम से कुल आठ मुकाबले खेलेगी। ये सभी मैच साई नेताजी सुभाष सदर्न सेंटर में आयोजित किए जाएंगे। इस सीरीज दोनों देशों की टीमों को एशिया कप के साथ ही भविष्य के अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों, विशेष रूप से जूनियर एशिया कप, की तैयारी का भी अवसर मिलेगा। इस दौरे का लक्ष्य खिलाड़ियों को उच्च-स्तरीय अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का अनुभव करना और भारत व मलेशिया के बीच मौजूदा खेल संबंधों को और बेहतर बनाना है।

भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच फ्रेडरिक सोयेज ने कहा है कि इस सीरीज से टीम को काफी लाभ होगा। उनके अनुसार ये मुकाबले जूनियर एशिया कप की तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। उन्होंने कहा, बेल्जियम दौरे के दौरान हमारे प्रदर्शन में निरंतर आया था, और अब मलेशिया के खिलाफ यह घरेलू सीरीज से टीम की तैयारी और बेहतर होगी। सोयेज ने साथ ही कहा, पिछले सप्ताह के गहन प्रशिक्षण शिविर में जिन रणनीतिक क्षेत्रों पर हमने काम किया है, उन्हें मैच हालातों में आंकने का अच्छा अवसर होगा, जिससे हमें अपनी टीम की ताकत और कमजोरियों को समझने में सहायता मिलेगी। हाल ही में बेल्जियम दौरे से लौटी भारतीय जूनियर टीम ने वहां कई मजबूत अंतरराष्ट्रीय टीमों के खिलाफ खेलकर अच्छा खासा अनुभव हासिल किया है। अब मलेशिया के विरुद्ध आठ मैचों की इस सीरीज से टीम संयोजन, खेल रणनीति को अंतिम रूप देने और खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आंकलन करने में सहायता मिलेगी। इन आठ मुकाबलों में से पांच मैच मलेशियाई अंडर-21 टीम भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के खिलाफ खेलेगी, जबकि शेष तीन मुकाबले साई टीम के साथ होंगे। यह दौरा निश्चित रूप से दोनों टीमों के युवा खिलाड़ियों के लिए एक अमूल्य सीखने का अनुभव साबित होगा और उन्हें आगामी जूनियर एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंटों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार करेगा।

अकीब से पहले जम्मू-कश्मीर के रसूल और उमरान ने बनायी थी भारतीय टीम में जगह

मुम्बई। जसप्रीत बुमराह के बाहर होने से अब 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ शुरु हो रही टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल युवा तेज गेंदबाज आकिब नबी जम्मू-कश्मीर के पहले क्रिकेटर नहीं हैं। अकीब राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने वाले राज्य के तीसरे क्रिकेटर हैं। जम्मू-कश्मीर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहले खिलाड़ी परवेज रसूल थे, जिन्होंने 2014 में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। रसूल मीरपुर में अपने पहले एकदिवसीय मैच में दो विकेट लेने में सफल रहे थे। हालांकि, उनका अंतरराष्ट्रीय करियर छोटा रह रहा और भारत के लिए उन्होंने केवल दो मैच एक एकदिवसीय और एक टी20 खेले। जनवरी 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ कानपुर में उन्होंने अपना एकमात्र टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला, जिसमें एक विकेट हासिल किया। 37 वर्षीय परवेज अब संन्यास ले चुके हैं और वह आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु सहित तीन टीमों का प्रतिनिधित्व करने वाले जम्मू-कश्मीर के भी पहले खिलाड़ी थे, जहां उन्होंने कुल 11 मैच खेले। परवेज के बाद, उमरान मलिक जम्मू-कश्मीर से टीम इंडिया में जगह बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। उन्होंने जून 2022 में अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया और कुल 18 अंतरराष्ट्रीय मैचों (10 वनडे, 8 टी20) में 24 विकेट लिए। उमरान ने आईपीएल 2022 में 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर भारतीय क्रिकेट में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया था, जो आईपीएल में किसी भारतीय द्वारा फेंकी गई सबसे तेज गेंद है। हालांकि, जुलाई 2023 के बाद से वह भारत के लिए कोई मैच नहीं खेल पाए हैं। कूल्हे की चोट के कारण लगभग डेढ़ साल तक क्रिकेट से दूर रहने और अपनी रफ्तार में कुछ कमी आने के बावजूद, 26 वर्षीय उमरान अभी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वापसी की उम्मीद पाले हुए हैं। उन्होंने आईपीएल में 26 मैचों में 29 विकेट हासिल किए हैं।

केंद्रीय खेलमंत्री मंडाविया ने अनाहत सिंह और जूनियर स्क्वैश टीम को किया सम्मानित

नई दिल्ली

केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ियों और टीम का सम्मान किया। इस दौरान महिला एकल में स्वर्ण पदक जीतने वाली अनाहत सिंह तथा कांस्य पदक विजेता भारतीय जूनियर पुरुष टीम के सदस्य आर्यवीर देवान, युशा नफीस और गुरवीर सिंह को सम्मानित किया गया।

18 वर्षीय अनाहत सिंह ने पिछले सप्ताह कनाडा में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। वह इस प्रतियोगिता में विश्व जूनियर महिला एकल का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनीं। यह उनका इस प्रतियोगिता में पांचवां अभियान था और विश्व जूनियर चैंपियनशिप में दूसरा पदक भी। इससे पहले उन्होंने 2025 में काहिरा में कांस्य पदक जीता था। सम्मान समारोह के दौरान खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए डॉ. मंडाविया ने उन्हें हालिया सफलता को लंबे सफर की शुरुआत मानने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अब खिलाड़ियों का अगला लक्ष्य एशियाई खेल 2026 और लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 होना चाहिए। अनाहत सिंह की ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना करते हुए डॉ. मंडाविया ने कहा कि उनका स्वर्ण पदक देश के लाखों युवाओं को स्क्वैश अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। इस अवसर पर अनाहत सिंह ने खेल मंत्री को अपने हस्ताक्षर वाला स्क्वैश रैकेट और स्क्वैश बॉल भेंट की। समारोह के दौरान खिलाड़ियों ने डॉ. मंडाविया के साथ सेल्फी भी ली और अनौपचारिक बातचीत की, जिससे कार्यक्रम का माहौल आत्मीय और उत्साहपूर्ण बन गया।

अनुज और अबु बने चैंपियन, आराध्या ने जीते दो खिताब

इंदौर। इंदौर जिला टेबल टेनिस संगठन की तृतीय जिला रैंकिंग टेबल टेनिस स्पर्धा में अनुज सोनी, अबु बकर और आराध्या राजपूत ने खिताबी सफलता हासिल की। पुरुष एकल में अनुज चैंपियन बने, जबकि अबु बकर ने बालक अंडर-19 और आराध्या ने महिला एकल व बालिका अंडर-19 वर्ग में दोहरा खिताब जीता। अभय प्रशाल स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित स्पर्धा के पुरुष एकल फाइनल में अनुज सोनी ने पंकज विश्वकर्मा को 3-1 से पराजित किया। सेमीफाइनल में अनुज ने कार्तिकेय कौशिक को 3-2 और पंकज ने अबु बकर को 4-0 से हराया। महिला एकल फाइनल में आराध्या राजपूत ने हिया पटेल को 4-1 से शिकस्त दी। बालिका अंडर-19 वर्ग के फाइनल में भी आराध्या ने हिया को 3-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। सेमीफाइनल में हिया ने भाग्यश्री दवे को 3-0 और आराध्या ने अक्षिता मित्तल को 3-0 से पराजित किया। बालक अंडर-19 वर्ग के फाइनल में अबु बकर ने रिदम गढ़िया को 3-1 से मात देकर खिताब जीता। सेमीफाइनल में अबु ने रक्षत चावड़ा और रिदम ने अभि जैन को समान स्कोर 3-1 से हराया।

फील्डिंग कोच टी दिलीप को रोहित ने असली हीरो करार दिया

मुम्बई

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा फील्डिंग कोच टी दिलीप की विदाई पर भावुक हो गये। रोहित ने दिलीप को असली हीरो करार दिया है। दिलीप का भारतीय टीम के साथ पांच साल का अनुबंध समाप्त हो गया है। ऐसे में उन्हें फील्डिंग कोच का पद छोड़ना पड़ा है। उनकी विदाई के दौरान खिलाड़ी भी भावुक हो गये और सभी ने उनकी प्रशंसा की। दिलीप ने टीम के साथ अपने कार्यकाल के दौरान खिलाड़ियों के फील्डिंग कौशल को निखारने में अहम भूमिका निभाई और ड्रेसिंग रूम में एक अच्छा माहौल भी बनाए रखा।

रोहित ने सोशल मीडिया में दिलीप के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, आप एक लीजेंड हैं। आपने ग्रुप के अंदर जादू भर दिया और आप पर्दे के पीछे मेहनत करने वाले असली हीरो हैं। आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं।' रोहित के ये शब्द उनकी दोस्ती की गहराई और टीम में दिलीप के योगदान के प्रति उनके प्रति सम्मान को दिखाते हैं। दिलीप एक कोच के साथ ही ड्रेसिंग रूम में उत्साह और सकारात्मकता का संचार करने वाले एक महत्वपूर्ण सदस्य भी थे।

गौरतलब है कि दिलीप साल 2021 में भारतीय टीम के सपोर्ट स्टाफ से जुड़े थे और उन्होंने तब से लेकर 2024-25 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के अंत तक अपनी सेवाएं दीं। उन्होंने पहले राहुल द्रविड़ और उसके बाद गौतम गंभीर दोनों के कार्यकाल के दौरान भारत के फील्डिंग कोच के रूप में काम किया। उनका अनुबंध् कई बार बढ़ाया गया, जिससे अंदाज होता है कि वह टीम के लिए उनके महत्व पूर्व रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में भारतीय टीम की फील्डिंग में काफी सुधार देखा गया, जिसने कई महत्वपूर्ण मैचों में टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।

टीम इंडिया से विदाई के बाद, टी दिलीप ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक लंबा और भावुक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने बीसीसीआई और टीम का आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, 'पांच साल के उस सफर के लिए सही शब्द ढूंढना मुश्किल है जो मेरे लिए इतनी मायने रखती है। मुझे इस टीम के सफर का हिस्सा बनने का मौका देने के लिए में बोर्ड का अभारी हूंहै।

राष्ट्रमण्डल खेलों के पदक विजेताओं का स्वदेश पहुंचने पर भव्य स्वागत

खिलाड़ियों ने जताया आभार

नई दिल्ली

राष्ट्रमण्डल खेलों में शानदार प्रदर्शन कर चौथे स्थान पर रहा भारतीय दल स्वदेश पहुंच गया। टीम का दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट पहुंचने पर पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रशंसकों के साथ ही खेल अधिकारी और समर्थक ढोल-नगाड़ों, फूल-मालाओं और भारत माता की जय के नारे लगाते दिखे।

वहीं इस सम्मान से अभिभूत खिलाड़ियों ने इस सम्मान पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह स्वागत उनके लिए किसी सपने से कम नहीं है और वे आगे भी देश के लिए इसी तरह पदक जीतने का प्रयास करेंगे।

इन खेलों में भारतीय मुक्केबाजों ने एतिहासिक प्रदर्शन किया। मुक्केबाजी फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि इन खेलों के 96 साल के इतिहास में भारत ने पहली बार मुक्केबाजी में सात स्वर्ण पदक जीते हैं। ये देश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ व सभी सहयोगी संस्थाओं को दिया है।

इस दौरान स्वर्ण पदक विजेता भारतीय मुक्केबाज साक्षी चौधरी ने एयरपोर्ट पर मिले शानदार स्वागत पर खुशी जतायी। उन्होंने भारत सरकार, मुक्केबाज फेडरेशन ऑफ इंडिया और हरियाणा सरकार द्वारा दिए गए निरंतर सहयोग और बेहतर प्रशिक्षण के लिए आभार व्यक्त किया। साक्षी ने अपना स्वर्ण पदक देशवासियों को समर्पित करते हुए कहा कि यह उपलब्धि पूरे भारत की है और वे भविष्य में भी देश के लिए बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगी।

वहीं मुक्केबाज प्रीति पवार ने भी टीम के प्रदर्शन और देश लौटने पर मिले सम्मान पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने सेना और भारत सरकार से मिले सहयोग को खिलाड़ियों की सफलता का प्रमुख कारण बताया। इसके अलावा एक अन्य मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने अपनी सफलता का श्रेय भारतीय सेना, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट और कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस को दिया। दूसरे ओर पुरुषों की 90 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक विजेता मुक्केबाज नरेंद्र बेरवाल ने कहा कि वे एशियाई खेलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

भारतीय पैरा-एथलीटों ने भी कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन किया। पुरुषों की शॉट पुट एफ-57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता सोमन राणा ने अपनी जीत को पूरे देश, भारतीय सेना और सभी सहयोगियों को समर्पित किया। उन्होंने भी एशियाई खेलों को अपना अगला लक्ष्य बताया।

सत्यमेव जयते

Government of Assam

LOK KALYAN DIWAS

Assam pays tribute to the architect of modern Assam

BHARAT RATNA
LOKPRIYA GOPINATH BORDOLOI

on his 76th death anniversary

LOK SEWA AWARD

KARMASHREE AWARD

To honour State Government employees who have diligently followed the ideals of

Lokpriya Gopinath Bordoloi

Government of Assam is pleased to bestow

KARMASHREE AWARD 2026

Category I Awardees

LAKHIMI MISTRI

Shri Dhrubajyoti Nath, ACS Joint Commissioner, Panchayat & Rural Development, Assam	Member : **Shri Ranjit Goswami,** APRDS, Assistant Development Commissioner, P&RD

MATSYA PARIPUSTI

	Members:	
Sri Deba Kumar Mishra, ACS District Commissioner, Kamrup	**Smt. Geetashri Lachit**, ACS, ADC, Kamrup **Dr. Sanjay Sarma**, DFDO, Kamrup	**Sri Tapan Kalita**, DEEO, Kamrup **Sri Bhupendra Bhattacharjya**, DSWO, Kamrup

MINING SECTOR REFORMS

Shri Ajay Tewari, IAS Additional Chief Secretary to the Govt. of Assam, Mines and Minerals Department.	Members: **Sri Pranjit Kr Wary**, ACS, Secretary to the Govt. of Assam, Mines and Minerals Department. **Sri Paragmoni Mahanta**, ACS, Director, Directorate of Geology and Mining, Assam. **Smt. Barnalee Nath**, Joint Director, Directorate of Geology and Mining, Assam

CHIRAYU CHARAIDEO

Dr. Neha Yadav, IAS District Commissioner, Charaideo	Members: **Shri Soroj Sonowal**, ACS, ADC, Charaideo **Smt. Suntrishna Gharphalia**, ACS, ADC, Sivasagar **Shri Vivek Sharma**, ACS, Assistant Commissioner, Charaideo

AYUSHMAN ASOM-MUKHYA MANTRI LOK SEVAK AROGYA YOJANA (AA-MMLSAY)

Dr. Siddharth Singh, IAS Chief Executive Officer, Atal Amrit Abhiyan Society, Assam	Member: **Shri Kamaljit Talukdar**, ACS, Jt. Chief Executive Officer, Atal Amrit Abhiyan Society, Assam

RESTORATION OF RESERVE FOREST & HUMAN-ELEPHANT CONFLICT MITIGATION.

Shri Tejas Mariswamy, IFS Divisional Forest Officer, Goalpara Forest Division (T)	Member: **Shri Gautam Gope**, Deputy Ranger, Goalpara Forest Division

MISSION BASUNDHARA 3.0 , SVAMITVA & SCHEDULE TRIBES & OTHER TRADITIONAL FOREST DWELLERS (RECOGNITION OF FOREST RIGHTS)

Shri Rahul Suresh Javir, IAS District Commissioner, Dhemaji	Members: **Shri Kailash Karthik N** , IAS, Director of Land Records & Surveys,etc., Assam **Shri Anand Malhotra**, IAS, Jt. Secy, Finance (Then CDC, Jonai Co-District, Dhemaji) **Dr. Sanjib Kumar Phukon**, ACS, Joint CEO, Govt. of Assam (Then ADC, Revenue & Forests, Dhemaji) **Dr. Bharat Konwar**, ACS, ADC (Revenue and Forest), Dhemaji **Shri Rituraj Sharma** , AFoS, Range Forest Officer, Dhemaji Range

SUSRUSHA SETU

Dr P. Ashok Babu, IAS, Commissioner & Secretary, Health & Family Welfare Department	Members: **Dr. Abhijit Sarma**, Executive Director, National Health Mission, Assam **Dr. Rahul Kumar Sarmah**, State Programme Officer, NCD Division, NHM, Assam **Smti. Lakhimi Dutta**, ACS, Joint Secretary, Health & Family Welfare Department

BAGURUMBA DWHOU 2026

Shri Rahul Chandra Das , ACS Director of Cultural Affairs, Assam	Members : **Shri Manvendra Pratap Singh**, IAS, (the then Commissioner of Transport,Assam) **Shri Sumit Sattawan**, IAS (the then DC, Kamrup (M)) **Shri Deba Kumar Misra** , ACS, DC, Kamrup

ESTABLISHMENT OF A CENTRE OF EXCELLENCE ON LAND ADMINISTRATION UNDER DILRMP

Shri Prabir Kumar Dutta, ACS, Principal, Assam Survey & Settlement Training Centre Cum Director, Centre of Excellence On Land Governance, Guwahati Centre

Category II Awardees

SRIBHUMI MISSION HSLC 2026

Shri Pradeep Kumar Dwivedi, IAS District Commissioner, Sribhumi	Members: **Rasika Islam**, ACS, Assistant Commissioner, Sribhumi **Neelam Jyoti Das**, Inspector of Schools, Sribhumi **Mahul Chowdhury**, Principal, DIET, Sribhumi

INNOVATION IN PUBLIC ADMINISTRATION THROUGH STRENGTHENING HIV PREVENTION, CARE, TREATMENT, DIGITAL GOVERNANCE

Dr. Indranoshee Das, ACS
Project Director, Assam State AIDS Control Society (ASACS), Health & Family Welfare Department

SMART METERING SCHEME UNDER RDSS

Shri Rakesh Kumar , IAS, MD, APDCL	Members: **Shri Sanidhya Baruah**, GM (Smart Grid) **Shri Pranjal Kotoky**, (the then CEO , Nagaon Circle) **Shri Pallab Pran Bora**, (the then CEO, Sivasagar Circle)

5 August 2026 **3:00 pm onwards**

Sri Sri Damodaradeva International Auditorium Panjabari, Guwahati

LOK SEWA AWARD 2026

State Level Lok Sewa Awardees, 2026

- Smti. Banashree Medhi, Assistant Section Officer
  Administrative Reforms, Training, Pension & Public Grievances Department
- Shri. Dhanjit Das, Junior Administrative Assistant
  Border Protection and Development Department
- Shri. Himon Jyoti Bez, Assistant Section Officer
  Personnel (A) Department
- Smti. Jyotirekha Das, Senior Assistant
  Assam Police Headquarters
- Shri. K. Prakash Singha, Assistant Section Officer
  General Administration Department
- Smti. Minakshi Sinha Das, Accountant(I)
  Fire & Emergency Services, Assam
- Smti. N. Hemi Devi, Assistant Section Officer
  Industries, Commerce & Public Enterprise Department
- Shri. Prasanta Engleng, Multi Tasking Staff
  O/o the District Fishery Development Officer, Kamrup (M)
- Shri. Ranjan Das , Accountant
  O/o the Directorate of Sports and Youth Welfare, Assam
- Smti. Sneha Ganguly, Assistant Section Officer
  Information Technology Department

District Level Lok Sewa Awardees, 2026

Baksa
Shri. James Kerketta, Senior District Administrative Assistant
O/o the District Commissioner, Baksa

Barpeta
Shri. Rajib Kumar Das, Senior Assistant
O/o the Senior Superintendent of Police, Barpeta

Biswanath
Shri. Joseph Barju, Junior District Administrative Assistant
O/o the District Commissioner, Biswanath

Bongaigaon
Shri. Prasanta Kumar Barman, Senior District Administrative Assistant
O/o the District Commissioner, Bongaigaon

Cachar
- Shri. Sujaybir Deb, Junior District Administrative Assistant
  O/o the District Commissioner, Cachar
- Smt. Shanti Lata Topno, Staff Nurse
  O/o the Joint Director of Health Services, Cachar

Charaideo
- Smti. Mitali Mohan, Senior District Administrative Assistant
  O/o the District Commissioner, Charaideo
- Shri. Ramesh Lal Das, Peon
  O/o the District Commissioner, Charaideo

Darrang
Shri. Prabin Saharia, Process Server
O/o the District Commissioner, Darrang

Dhemaji
Shri. Prasanna Bhuyan, Junior District Administrative Assistant
O/o the District Commissioner, Dhemaji

Dibrugarh
Shri. Gunjalal Handique, Senior District Administrative Assistant
O/o the District Commissioner, Dibrugarh

Dima Hasao
Shri. Jatan Kempray, Multi Tasking Staff
O/o the District Commissioner, Dima Hasao

Goalpara
Shri. Bhuban Prosad Rabha, Senior District Administrative Assistant
O/o the District Commissioner, Goalpara

Golaghat
- Shri. Munin Chandra Gogoi, Upper Division Assistant
  O/o the District Institute of Education & Training (DIET), Golaghat, Dergaon
- Shri. Bichitra Saikia, Multi Purpose Worker (M)
  O/o Negheriting S/C

Hailakandi
- Shri. Hirendra Kumar Roy, Senior District Administrative Assistant
  O/o the District Commissioner, Hailakandi
- Shri. Arun Jyoti Dey, Senior District Administrative Assistant
  O/o the District Commissioner, Hailakandi
- Shri. Nazmul Islam Tapadar , Senior District Administrative Assistant
  O/o the District Commissioner, Hailakandi

Jorhat
Shri. Sarupai Das , Gr-IV
O/o the District Commissioner, Jorhat

Kamrup
- Shri. Niranjan Ch. Baro, District Administrative Supervisory Assistant, O/o the District Commissioner, Kamrup
- Shri. Bhupen Das, Senior Assistant
  O/o the District Malaria Officer, Kamrup

Kamrup(M)
Shri Achyutananda Das, Senior District Administrative Assistant –cum- Nazir
O/o the District Commissioner, Kamrup (M)

Karbi Anglong
- Smti. Rashmi Basumatary, Senior District Administrative Assistant
  O/o the District Commissioner, Karbi Anglong
- Shri. Phukan Tisso, Office Peon (Grade-IV),
  O/o the District Commissioner, Karbi Anglong

Kokrajhar
- Smti. Lina Brahma , Senior District Administrative Assistant
  O/o the District Commissioner, Kokrajhar
- Shri. Lohit Sarkar, Khalashi (Gr-IV)
  O/o the Executive Engineer, Gossaigaon- Kokrajhar West Division (Irrigation) Gossaigaon.

Lakhimpur
Shri. Nirmal Chandra Panging, Head Assistant
O/o the Sr. Superintendent of Police, Lakhimpur

Morigaon
Smti. Mina Kumari Devi, Senior District Administrative Assistant
O/o the District Commissioner, Morigaon

Nagaon
Smti. Debajani Borah, Senior District Administrative Assistant
O/o the Co- District Commissioner, Kaliabor

Nalbari
- Shri. Hiren Deka, Senior District Administrative Assistant
  O/o the District Commissioner, Nalbari
- Shri. Gitartha Kumar Nath, Junior District Administrative Assistant
  O/o the District Commissioner, Nalbari

Sivasagar
- Shri Nitya Dutta, Senior District Administrative Assistant
  O/o the District Commissioner, Sivasagar
- Smti. Namita Kathar, Senior Assistant
  O/o the Executive Engineer, PWD, Sivasagar , District Territorial Building Division, Sivasagar
- Shri. Ashim Jyoti Khound, Stenographer
  O/o the Chief Executive Officer, Zila Parishad, Sivasagar

Sonitpur
Shri. Jibon Bora, Physical Instructor
O/o the District Sports Officer, Sonitpur

Tinsukia
- Smti. Junamoni Kalita, District Administrative Head Assistant
  O/o the Co-District Commissioner, Sadiya
- Shri. Jotin Sonowal, Senior District Administrative Assistant
  O/o the Co-District Commissioner, Sadiya
- Shri. Khupmin Guite, Junior Assistant
  26 Assam, Battalion NCC, Digboi

Udalguri
- Smti. Gitanjali Ojah, Senior District Administrative Assistant
  O/o the District Commissioner, Udalguri
- Shri. Sachindra Deka, Jarikarak
  O/o the District Commissioner, Udalguri

West Karbi Anglong
Smti. Preeti Terangpi , Junior Assistant
O/o the District Commissioner, West Karbi Anglong

-- DIPR /DIVBS-47/5-Aug-26